RNI No. DELMUL/2012/47011

25 जून, 2026 गुरूवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 85

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अभिषेक पोरेल पर लगे यौन शोषण के आरोप 07

संक्षिप्त वार्ता

ट्विशा शर्मा मौत मामले में एम्स पहुंची सीबीआई

भोपाल, वेब वार्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज करते हुए दिल्ली से आई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम मंगलवार को एम्स भोपाल पहुंची।

टीम ने करीब दो घंटे तक अस्पताल परिसर में रहकर पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल की और संबंधित डॉक्टरों व स्टाफ से पूछताछ की। इसके अलावा हर तरह के मेडिकल एंगल पर डॉक्टर्स से बातचीत भी की। जानकारी के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने टीम ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से पूछताछ करते हुए यह जानने की कोशिश की कि मरीज को किस हालत में लाया गया। इसके साथ ही सीबीआई ने पोस्टमॉर्टम से जुड़े डॉक्टरों से भी विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया, रिपोर्ट तैयार करने के आधार और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं को लेकर सवाल-जवाब किए।

रिहाई के लिए पीएमओ में लगाई गुहार

वेब वार्ता, रामनगर। ब्रिटेन में कैद चिल्किया गांव निवासी कैप्टन अजय पंत की रिहाई के लिए पौड़ी सांसद अनिल बलूनी व नैनीताल-ऊधम सिंह नगर के सांसद अजय भटट भी आगे आए हैं। उन्होंने इस संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। अजय के पिता वीसी पंत ने दिल्ली पीएमओ में उपसचिव मंगेश घिल्डियाल से भी फोन कर गुहार लगाई है। रूस से शिप में क्रूड आयल लेकर गुजरात लौट रहे रामनगर निवासी कैप्टन अजय पंत को इंग्लिश चैनल पार करते समय ब्रिटिश सशस्त्र बल ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से परिवार परेशान है।

रिश्ते तभी चलेंगे जब दोनों देश एक दूसरे को इज्जत देंगे

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की हाई-प्रोफाइल बैठक में जब दुनिया के कई बड़े देश एकजुट हुए, तो सबकी निगाहें भारत और चीन पर टिकी थीं। इसी महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंचे थे। बातचीत की मेज पर बैठते ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ड्रैगन की आँखों में आँखें डालकर बिल्कुल दो टूक शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। डोभाल ने यह साफ कर दिया कि भारत और चीन के रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब दोनों तरफ से बराबर की इज्जत होगी, क्योंकि एकतरफा तानाशाही का दौर अब पुराना हो चुका है और भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। यह संदेश 2020 में पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर हुए हिंसक सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने के प्रयासों के बीच आया है।

जो एक बार मध्यप्रदेश आता है, वह यहीं का होकर रह जाता है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्यप्रदेश देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में है शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समय तभी बदलता है, जब संकल्प बड़ा होता है। सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का समय बदला है। विश्व के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री श्री मोदी को विभूषित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकसित भारत @ 2047 और अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का संकल्प लिया है।

वेब वार्ता, भोपाल

राज्य सरकार 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को ला चुकी है धरातल पर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ और एमओयू साइन हुए। यह प्रसन्नता का विषय है कि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार धरातल पर ला चुकी है। मध्यप्रदेश की छवि कृषि प्रधान राज्य के साथ उद्योग मित्र राज्य की भी बनी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार को समर्पित किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय युवा प्रतिभाओं ने दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचकर भारत का मान बढ़ाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। राज्य सरकार ने भी अपनी स्पेस-टेक पॉलिसी लॉन्च की है। मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर किया उनका स्मरण

विकसित भारत @ 2047 में 2 ट्रिलियन डॉलर का होगा मध्यप्रदेश का योगदान

राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि इसमें से लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान मध्यप्रदेश का हो। मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवा, सुशासन और जन कल्याण के संकल्पों को पूर्ण करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश की गिनती देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में हो रही है। हम विरासत भी और विकास भी के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विकसित मध्यप्रदेश विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से राज्य में मौजूद निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की विशेषता है कि एक बार जो मध्यप्रदेश आता है, यहीं का होकर रह जाता है। कार्यक्रम में उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि, निवेशक, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि तथा नीति निमार्ता शामिल हुए।

प्रदेश में पिछले तीन साल से विकास का कारवां लगातार बढ़ रहा है आगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन साल से विकास का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त लैंड बैंक है। राज्य सरकार ने उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने लिए पारदर्शी और उद्योग मित्र नीतियां लागू की हैं। मध्यप्रदेश की इन्हीं विशेषताओं के कारण निवेशक उद्योग लगाने के लिए राज्य में आ रहे हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण उन्हें कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का विशेष लाभ भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने चारों दिशाओं में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अधोसंरचना विकास पर विशेष बल दिया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: एसआईटी ने चंपत राय सहित 17 को आरोपी माना, एफआईआर तय

चंपत राय के करीबी के संपत्ति में बंपर आया उछाल

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा कर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव सहित 17 लोगों को आरोपी माना है। सूत्रों के मुताबिक, इन सभी के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज होना लगभग तय है।

जांच के दौरान, एसआईटी टीम को दानपात्रों की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिली हैं, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत है। टीम मंगलवार को फिर जांच के लिए अयोध्या पहुंच सकती है। एसआईटी ने लगभग 150 इसतरह के सेवादारों और कर्मचारियों को चिह्नित किया है जिनकी आर्थिक स्थिति 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक काफी सुधर गई। इसमें चंपत राय के करीबी फूलकांत मिश्रा भी शामिल हैं, जिनके पास 25 लाख रुपये की कुल कीमत वाली तीन लग्जरी कारें मिली हैं। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी 20 पन्नों की शुरूआती जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसमें 150 लोगों से पूछताछ का विवरण है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दुबारा गठित करने की सिफारिश की गई है।

संजय राउत का गद्दारों के खिलाफ युद्ध का ऐलान

मुंबई। शिवसेना-यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने के बाद, पार्टी नेता संजय राउत ने गद्दारों के खिलाफ सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यह घटनाक्रम ऑपरेशन टाइगर के तहत सामने आया, जब उद्धव गुट के इन सांसदों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की।

राज्यसभा सांसद राउत ने पोस्ट में आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने लिखा, ना थके कभी जोड़ी, ना हिम्मत हारी है। लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ, हौसला है बुलंद, सफर जारी है। इस पोस्ट में राउत की राइफल पकड़े हुए तस्वीर भी थी, जो उनके दृढ़ संकल्प को दशार्ती है।

गंगा दशहरा शुरू, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी

हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में तीन स्थानों कच्चा घाट लठीरा, पुष्पावती पूठ एवं तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा दशहरा पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मां गंगा शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण ज्येष्ठ मास का गंगा दशहरा पर्व का स्नान दोबारा हो रहा है। तीर्थ नगरी ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा तथा पुष्पावती पूठ में बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं।

वहीं अनेक श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर गरीब एवं असहाय लोगों में अन्न, वस्त्र एवं धन आदि का दान कर रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी अनांउसमेंट करने के साथ ही मोटर बोट से गश्त कर रहे हैं। गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। पुलिस कर्मी सादी वर्दी में लगातार निगरानी कर रहे हैं। हाईवे से लेकर पार्किंग एवं गंगा तट तक पुलिस का पहरा है। सीसीटीवी के जरिए गंगा तट पर नजर रखी जा रही है।

बता दें गंगा स्नान करने के लिए अनेक श्रद्धालु मंगलवार देर शाम से ही तीर्थ नगरी में पहुंचना शुरू हो गए थे। इसके कारण धर्मशाला एवं होटल आदि पहले ही फुल हो गए। पुरुषोत्तम मास में मुंडन, गंगा पूजन, विवाह आदि धार्मिक कार्य नहीं होते हैं।

रोनाल्डो सभी छह विश्वकप में गोल दागने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने

ह्यूस्टन। पुर्तगाल के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बड़ा रिकार्ड अपने नाम किया है। 41 साल के रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में गोल दागते ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अब रोनाल्डो सभी छह विश्वकप में गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गये हैं। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत हासिल की। ह्यूस्टन में खेले गये इस मैच में रोनाल्डो ने खेल के छठे मिनट में ही गोल दागकर सभी छह विश्कवप में गोल का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद, उन्होंने 39वें मिनट में अपना दूसरा गोल भी किया, जिससे टीम की जीत तय हो गयी। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

भूमि खरीद विवाद पर घिरे मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव

कांग्रेस बोली-निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री दें इस्तीफा

भोपाल, वेब वार्ता

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन घोटाले से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा कलंक है और मेरा मानना है कि हाल ही में हुआ स्टिंग ऑपरेशन अद्भुत और अकल्पनीय था। मंत्रियों के लेन-देन की पूरी जानकारी दी गई। मंत्रियों के कार्यालयों के लेन-देन का विवरण भी दिया गया। आज जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं, उससे मुख्यमंत्री पूरी तरह सवालों के घेरे में हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम ने धर्मनगरी उज्जैन को जमीन के गोरखधंधे का हिस्सा बना दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम बताएं कि क्या ये सही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लॉट खरीदकर 168 एकड़ जमीन अर्जित की। लगभग 111 एकड़ जमीनें ऐसी जगहों पर खरीदी गई, जो परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र हैं। क्या ये महज संयोग है? क्या सरकार उन सारी परियोजनाओं के भूमि उपयोग परिवर्तन की सूची सार्वजनिक करेगी, जहां आपके परिवार ने जमीनें खरीदी? क्या आप ये घोषणा करेंगे कि इस भूमि सौदे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा न्यायिक जांच हो? कुल भूमि स्वामित्व रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लॉट (335 एकड़ जमीन) है।

क्यों नहीं हो रही है जांच

राज्य में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि ये आरोप नहीं हैं, ये आपके सामने सबूत हैं। मीडिया की रिसर्च रिपोर्ट जैसी है, हमने विधानसभा में भी कई बार यह मामला उठाया है। विधानसभा के अंदर सरकार कहती है कि वे जांच करवा रहे हैं, तो जांच क्यों नहीं हो रही है।

कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि जब मोहन यादव शिक्षा मंत्री बने थे, तब उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। आज खबरों के अनुसार, उनके पास 250 एकड़ जमीन है। एक और बात जो अब चर्चा में है, वह यह है कि उनके एमएलए प्रतिनिधि ने हाल ही में बहुत कम समय में 65 एकड़ जमीन खरीदी। जो विवरण सामने आए हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं और दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति की संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 20-25 वर्षों में मध्य प्रदेश में राजनेताओं द्वारा खरीदी गई जमीन को देखें, तो हमारे सर्वे और चल रही रिसर्च से जो नतीजे सामने आए हैं। वे सचमुच हैरान करने वाले हैं और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि जिन भी राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वहां पर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। कई आरोप लगते हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है। अब यह नया मामला सामने आया है। अगर सबूत मिले हैं, तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कम से कम नैतिक आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती। अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे इस्तीफा मंजूर हो या न हो, यह एक राजनीतिक मामला है, लेकिन उन्हें कम से कम इस्तीफा सौंप देना चाहिए ताकि जांच में उनकी कोई दखलंदाजी न हो और जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सके।

केरल में शिगेला का कोहराम

15 नए मरीजों के साथ जून में आंकड़ा 165 के पार

वेब वार्ता,तिरुवनंतपुरम

केरल में शिगेला बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य में इस खतरनाक संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक 8 मरीज अकेले कोझिकोड जिले में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, केवल जून महीने में ही अब तक शिगेला के 165 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं, इस साल राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 241 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार को मिले 15 नए मामलों में कोझिकोड से 8, मलप्पुरम से 3, वायनाड से 2, जबकि कन्नूर और कोल्लम से 1-1 मरीज शामिल है। जून के महीने में कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड जिलों में संक्रमण की रफ्तार सबसे डराने वाली रही है।

अकेले कोझिकोड में अब तक 57 मामले सामने आने के बाद वहां आउटब्रेक (महामारी का प्रकोप) घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा वायनाड में 22, त्रिशूर में 12 और अलप्पुझा में 3 मामलों पर स्वास्थ्य विभाग विशेष नजर रख रहा है। राज्य के अन्य प्रभावित जिलों में मलप्पुरम (24), तिरुवनंतपुरम (17), कन्नूर (11), कोल्लम (10), इडुक्की (3), एनार्कुलम (3) और पलक्कड़ (3) शामिल हैं।

चिकित्सकों के अनुसार, शिगेला एक बेहद संक्रामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन (जीवाणु संक्रमण) है। इसकी चपेट में आने पर मरीज को तेज बुखार, पेट में गंभीर ऐंठन, मरोड़ और दस्त (डायरिया) जैसी शिकायतें होती हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से दूषित पानी पीने, अस्वच्छ भोजन करने या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पानी उबालकर पीने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

इसी बीच, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में निपाह वायरस की स्थिति को लेकर भी ताजा जानकारी साझा की है। राहत की बात यह है कि निपाह संक्रमितों के संपर्क में आए 11 लो-रिस्क (कम जोखिम वाले) लोगों ने अपनी 21 दिनों की आइसोलेशन अवधि बिना किसी लक्षण के पूरी कर ली है, जिसके बाद उन्हें निगरानी से मुक्त कर दिया गया है।

संपादकीय

रद्द करो दलबदल कानून

आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) के सांसद दलबदल कर चुके हैं। आप के 7 सांसद राज्यसभा के थे, लेकिन अभी लोकसभा के 3 सांसदों की बोली तय नहीं हुई है। तृणमूल और उद्धव शिवसेना के 26 लोकसभा सांसद तोड़े जा चुके हैं। यानी बिक चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता पार्टी को इतना मासूम और तटस्थ करार देने का ढोंग न करें, क्योंकि सांसद उसके अघोषित ऑपरेशन दो-तिहाई के मद्देनजर तोड़े जा रहे हैं। नहीं तो बागियों की बैठकों में भाजपाई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री क्या करते रहे हैं? हररोज, हर पल चाय-पानी ही चलता रहता है क्या? बहरहाल शिवसेना (उद्धव) के बिकाऊ सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलीन हो चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह अब उसे ही असली शिवसेना मानते हैं। वह काफी हद तक उचित भी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे ही असली शिवसेना की मान्यता दी है और चुनाव चिह्न भी उसे ही सौंप दिया गया है। चुनाव आयोग सक्षम, अधिकार प्राप्त संवैधानिक संस्था है। इसी तरह शरद पवार ने जिस एनसीपी की स्थापना की थी, अब वह उनके सगे भतीजे अजित पवार (अब दिवंगत) के कब्जे में है। उसे ही असली एनसीपी की मान्यता प्राप्त है। चुनाव चिह्न भी उसे ही आवंटित किया जा चुका है। हालांकि ये दोनों मामले अभी सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन हैं। तृणमूल कांग्रेस में तो बागी 60-65 विधायकों ने सामूहिक निर्णय लेकर ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अरूप राय को नया अध्यक्ष चुन लिया है। कुछ उपाध्यक्ष और महासचिव भी तय किए गए हैं। कार्यकारिणी नई बनना भी तय लगता है। उसके बाद चुनाव आयोग की दहलीज पर दस्तक दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह का आशीर्वाद है, तो आयोग उसे भी असली तृणमूल घोषित कर देगा। गृहमंत्री का संकल्प है कि ममता की तृणमूल का सर्वनाश किए बिना वह राहत की सांस महसूस नहीं करेंगे।

तृणमूल के बागी 20 लोकसभा सांसद तो ह्यनेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडियाह्न सरीखी गुमनाम और बिन विधायक-सांसद की बौनी पार्टी में विलय कर चुके हैं। फिलहाल उनका प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला के विचाराधीन है। भाजपा तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी द्रमुक पर भी डोरे डाल रही है, क्योंकि लोकसभा में उसके 22 सांसद हैं। बेशक राज्य में उनकी सरकार पराजित हो चुकी है। अभी तो छोटे और 1-2 सांसद वाले दलों को खरीदना शेष है। ये तमाम दलबदल भीतरी असंतोष और नेतृत्व के प्रति बगावत के ही निष्कर्ष नहीं हैं, बल्कि सांसद तोड़े जा रहे हैं। 52वां और 91वां संविधान संशोधन कर जो दलबदल विरोधी कानून बनाया गया था, उसमें एक-तिहाई अथवा दो-तिहाई सांसदों-विधायकों के पालाबदल की व्यवस्था रही है। अब यह कानून कागजी साबित हो रहा है, क्योंकि जन-प्रतिनिधि बेचे-खरीदे जा रहे हैं। तो फिर इस कानून की जरूरत क्यों है? जैसा 1985 और 2003 से पहले था, वैसा ही रहने दीजिए। सांसदों-विधायकों को दलबदल करने की कानूनन छूट दे दी जाए। अरे, खुला बाजार सजा है, बोलियां लगने दीजिए। लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता की परवाह क्यों की जाए? अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका सरीखे बड़े लोकतांत्रिक देशों में दलबदल निरोधक कानून नहीं है।

फिर भी वहां इतना दलबदल नहीं होता, जिस व्यापक स्तर पर भारत में होता रहा है। उनके लिए राजनीतिक, चुनावी अनुशासन बेहद मायने रखता है। इस संदर्भ में, एक देशवासी होने के नाते, हमारा सुझाव है कि दलबदल कानून को रद्द कर दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यह सुझाव नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें दलबदल कराने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की आड़ चाहिए। वैसे भी देश में दलबदल की परंपरा पुरानी है और आजादी के पहले और उसके तुरंत बाद राजनीतिक दल टूट कर बिखरते और नए दल बनाए जाते रहे हैं। कांग्रेस टूटी, 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी टूट कर आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। और भी कई उदाहरण हैं। अब पहले से भी ज्यादा दलबदल होने लगा है।

नाकारा भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गए पंद्रह घरों के चिराग

राजधानी लखनऊ में पंद्रह असीम संभावनाओं से भरे बच्चों की एक अग्निकांड में जान चली गई। लखनऊ के अलीगंज में एक तीन मंजिला इमारत में जहां पालतू पशु दुकान, एनीमेशन और गेमिंग कोचिंग चलती थी जिसमें करीब 25–30 किशोरवय छात्र छात्राएँ पढ़ते थे जिन्होंने अपने भविष्य को गढ़ने के उद्देश्य से स्किल बढ़ाने के लिए इस कोचिंग में एडमिशन लिया था । एक हादसे में 15 किशोर बच्चे जान गंवा गए। यहां अपने जिगर के टुकड़ों को पढा लिखा कर भविष्य बनाने के लिए भेजने वाले अभिभावकों को सपने में भी गुमान नही रहा होगा कि यह कोचिंग संस्थान एक दिन लाक्षागृह बन जाएगा और उनके घर के चिराग इस भयानक हादसे में जीवन गंवा देंगे इस बेहद दर्दनाक हादसे में 15 युवाओं की दम घुटने से मौत हो गई।यह पंद्रह परिवारों के सपनों उम्मीदों की भी मौत हो गई है। ये परिवार इस त्रासद अग्निकांड की मार से इस जीवन में कभी भी नहीं उबर पाएंगे। इस अग्निकांड हादसे की भयावहता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15 छात्र छात्राओं की मौके पर ही आग से जलकर और धुएं से दम घुटने से मौत हो गई। जबकि सभी छात्र छात्राओं ने खुद को बचाने के लिए सभी प्रयास किए फिर भी वे कामयाब नहीं हो सके। वे बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सके। आधे दर्जन किशोर घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। आग से बचाव और बुझाने के लिए दमकल आधे घंटे बाद पहुंची जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। वहीं मुख्यमंत्री जो दौरे पर थे अपना दौरा छोड़कर मौके पर पहुंचे और उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक में घटना की समीक्षा की और मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए दो सदस्यीय एसआइटी गठित करने के आदेश दिए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार आग में एक युवक ने तो बिजली के जलते हुए तारों को पकड़कर नीचे कूदा। वहीं एक युवक जान बचाने के लिए शीशा तोड़कर कूद पड़ा लेकिन नीचे वह लोहे के ग्रिल पर गिर गया जिसकी वजह से वह गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसे लोग बचाकर अस्पताल ले गए। कुछ युवक जान बचाने के लिए बिल्डिंग में पीछे की ओर बाथरूम में चले गए लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं था। इसकी वजह से जब आग बढ़ी तो वे बाहर नहीं निकल सके क्योंकि आग सामने की ओर से लगी थी जो अत्यंत भयावह थी। देश में आग की घटनाएं अब रोजाना की बात हो गई हैं।कभी नर्सिंग होम और नवजात शिशु केयर सेंटर कभी अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों, कारखानों, होटल, रेस्तरां और झुग्गी बस्तियों यहां तक की चलती ट्रेन की बोगियों में आग के हादसे सामने आते रहे हैं जिनमें हर साल सैकड़ों जीवन आग की भेंट चढ़ जाते हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट कारण बताया जाता है, कहीं गैस सिलेंडर, कहीं बिजली उपकरणों की खराबी और कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी। रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ में पिछले महीने में बड़ी संख्या में आग की घटनाएं बिजली व्यवस्था की खामियों और ओवरलोडिंग से जुड़ी रही हैं। सवाल केवल आग लगने का नहीं है। सवाल यह है कि जिन इमारतों में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे और युवा आते हैं, वहां अग्निशमन यंत्रों की स्थिति क्या है? उनके चलाने का प्रशिक्षण लिया गया या नहीं? क्या आपातकालीन निकास द्वार मौजूद हैं? क्या भवनों का नियमित सुरक्षा ऑडिट होता है? क्या स्थानीय निकाय और अग्निशमन विभाग समय समय पर निरीक्षण करते हैं? और यदि करते हैं तो फिर ऐसी इमारतें संचालन की अनुमति कैसे प्राप्त कर लेती हैं? लखनऊ की घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि अधिकांश भवनों में सुरक्षा व्यवस्था कागजों तक सीमित है। जब संकट आता है तो लोग सीढ़ियों, खिड़कियों और पाइपों के सहारे अपनी जान बचाने को मजबूर हो जाते हैं।

हर बड़ी घटना की तरह ही इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न दलों के राजनेताओं की शोक संवेदना आयी और सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी की है लेकिन क्या एक जीवन की कोई भरपाई की जा सकती है? क्या जीवन का कोई भी मोल हो सकता है?

इस हादसे के शिकार बने कुछ बच्चे अभी जिंदगी के लिए अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं। आजादी के करीब अस्सी साल बाद भी इस देश की सरकारें व्यवस्था सिस्टम को नही सुधार सकी हर स्तर पर भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि आप ईमानदारी से भवन का निर्माण करें तो भी रिश्वत देना पड़ेगा फिर समझ नहीं आता कि बिना नक्शा राज्यों की राजधानियों में सरकार और अधिकारियों की नाक के तले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का नक्शा पास करा कर तीन मंजिला व्यवसायिक भवन इमारतों का निर्माण किस की कृपा से हो जाता है? कौन सा तंत्र है जिस के आशीर्वाद से इन इमारतों में बिना अग्निशमन विभाग व दूसरे विभाग की अनुमति के कोचिंग संस्थान या चाइल्ड नर्सरी या होटल संचालित किए जाते हैं? हर बड़े हादसे के बाद सहानुभूति मुआवजा राशि जांच कमेटी का गठन किया जाता है वायदा घोषणा की जाती है कि दोषियों को दंडित किया जायेगा हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी लेकिन कुछ नही बदलता इन घोषणाओं का फायदा वही अफसरशाही उठाती है जो जांच और कारवाई का नाटक कर तमाम वैध अवैध निमार्णों और प्रतिष्ठानों से उगाही करती है जेब भरती है और अगले हादसे का इंतजार करती है।

जाहिर है कि इन हादसों को रोका जा सकता है बशर्ते पंगु सिस्टम लचर व्यवस्था, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी कर अकूत संपत्ति जुटाने मे लगी सरकारी भ्रष्ट मशीनरी को नियंत्रित किया जाए मुद्दा आग नहीं है भ्रष्टाचार है भ्रष्ट अफसरशाही है जो सही काम की मंजूरी के भी पैसे लेती है और नियमविरूध्द कार्य को दोनों हाथ से रिश्वत बटोर कर संरक्षण देती है वहीं दस फीसदी मामलों में राजनीतिक नेताओं के ईशारे पर अवैध काम को स्वीकृति दे कर उनके भी आंख का तारा बनी रहती है। दरअसल यही व्यवस्था का दुरुपयोग है समाज में भ्रष्टाचार का घुन इस तरह से लग चुका है कि सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली में अस्पताल के निकट होटल कम गेस्ट हाउस में आग लगने से कई लोगों की जान चाली गई थी जिनमें से एक दर्जन से अधिक विदेशी नागरिक भी थे। रिकार्ड बोल रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के कई होटलों में इस प्रकार आग लग चुकी है इसके बावजूद कोई फायर सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भवन चूंकि तीन मंजिला था और कई मकान व भवन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नीचे से लेकर ऊपर तक उसमें व्यवसायिक कार्य हो रहे थे। भवन में दूसरा कोई रास्ता भी निकलने को नहीं था और आगे शीशे की बंद खिड़कियां थीं। आग को एसी ब्लास्ट या शार्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है।सवाल फिर वही है कि लखनऊ और दिल्ली जैसे अग्निकांडों के लिए जिम्मेदार कौन हैं? किसकी जवाबदेही है? दरअसल, शहरों में इतनी कम जगहों पर ऑफिस आदि चल रहे हैं कि जब वहां कोई हादसा हो जाता है, तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। कई बार आने और जाने का एक की रास्ता रहता है। रास्ते बहुत संकरे होते हैं। कम से कम जगह में ज्यादा लोग काम करते हैं। बचाव के साधन नदारद होते हैं। चश्मदीदों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम 30 से 40 मिनट की देरी से पहुंची। फायर बिग्रेड का इतनी देरी से पहुंचने का मतलब है आग का विकराल हो जाना। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है क्या सरकारों की इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नहीं है? हमारा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हादसे को एक चुनौती माने और सटीक कारवाई और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाएं जो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बने। दिवंगत बच्चों को इस से बेहतर कोई श्रद्धांजली नहीं हो सकती है।

(लेखक – मनोज कुमार अग्रवाल)
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 38 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

कामाख्या शक्तिपीठ का प्रसिद्ध अंबुबाची मेला

भारतवर्ष की पुण्यभूमि में विभिन्न भागों में 51 शक्तिपीठ स्थित हैं जिनके दर्शन पूजन से विविध मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है जो महाशक्तिपीठ कहलाता है कामाख्या देवी का मंदिर। यह मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी में एक पहाड़ी पर बना है। यह मंदिर अन्य शक्तिपीठों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न है क्योंकि यह स्थल तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्द है।

इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, यहां पर माता सती का योनि भाग गिरा था इसलिए यहां देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है जोकि शिला के रूप में विराजमान है। यहां नीलप्रस्तरमय योनि माता कामाख्या साक्षात निवास करती हैं। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन और स्पर्श करते हैं वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ मां भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इस शक्तिपीठ में देवी मां 64 योगनियों और दस महाविद्याओं के साथ विराजित हैं। भुवनेश्वरी, बगला, छिन्न मस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, धूमावती और भैरवी एक ही स्थान पर विराजमान हैं। यूं तो सभी शक्तिपीठों का अपना महत्व है पर अन्य सभी में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना जाता है। कलिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए तथा अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। यहां कामनारूपी फल की प्राप्ति होती है.

अम्बुबाची शब्द अम्बु और बाची दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसमें अम्बु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है उतफूलन। यह शब्द स्त्रियों की शक्ति और उनकी जन्म क्षमता को दशार्ता है। प्रतिवर्ष जून के महीने में यह मेला उस वक्त लगता है जब मां कामाख्या ऋतुमती रहती हैं। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भ गृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो

जाते हैं। तीन दिनों के उपरान्त मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के उपरान्त ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है।

यात्री पहले दिन कामेश्वरी देवी और कामेश्वर शिव के दर्शन करते हैं और तब महामुद्रा के दर्शन करते हैं। देवी का योनिमुद्रापीठ दस सीढ़ी नीचे एक गुफा में स्थित है जहाँ हमेशा अखंड दीपक जलता रहता है। यहाँ आने-जाने का मार्ग अलग बना हुआ है, यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपडा दिया जाता है जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में स्थित महामुद्रा के आस-पास सफेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं,तीन दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता के रज से रक्तवर्ण हो जाते हैं। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं इस वस्त्र को धारण करके उपासना करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तीन दिन के लिए लाल हो जाता है। कामाख्या में अम्बुबाचि पर्व के अलावा दो उत्सव और मनाए जाते हैं जिनमें से एक है देवध्वनि जिसे देऊधाबी कहते हैं,इसमें बाध्ययंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र में पुष्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है जिसमें कामेश्वर की चल मूर्ति को कामेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। दूसरे दिन भगवती के पंचरत्न मंदिर में दोनों मूर्तियों का हर-गौरी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले के दौरान तांत्रिक शक्तियों को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ सैंकड़ों तांत्रिक अपने एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं।अंबुबाची मेला भारत में शक्ति पूजा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व धरती मां की उर्वरता का प्रतीक है और मान्यता है कि इस दौरान देवी कामाख्या, जो स्त्री शक्ति और सृजन शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं, अपने वार्षिक रजस्वला काल से गुजरती हैं।

लेखक- कुमार कृष्णन

आपातकाल का अंत कितना भयावह : लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा

25 जून 1975 की आधी रात का काला अध्याय कैसे कोई भूल सकता है? गर्मी, तपिश और आंधी ने तो जनमानस को पहले से ही झुलसा रखा था ऊपर से रेडियो पर आया संदेश से पूरा देश सकते में आ गया। आपातकाल न तो पढ़ा था न पहले कभी देखा था अचानक आए राजनीतिक तूफान ने देश में अफरातफरी मचा दी। देश में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है।

लगभग 21 महीनों तक चले इस दौर ने न केवल राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए। मार्च 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, तब देश ने राहत की सांस तो ली, लेकिन इसके पीछे छिपी पीड़ा, भय और लोकतांत्रिक संस्थाओं को हुई क्षति लंबे समय तक महसूस की गई।आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है।

आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अखबारों को सरकारी अनुमति के बिना समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता नहीं थी। विरोधी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। हजारों राजनीतिक कार्यकताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया। लोकतंत्र की आत्मा मानी जाने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी।

आपातकाल के अंतिम चरण में सबसे अधिक आलोचना जबरन नसबंदी अभियान और झुग्गी–झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाइयों को लेकर हुई। कई स्थानों पर प्रशासनिक दबाव में लोगों को नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। गरीब और कमजोर वर्ग इस नीति का सबसे बड़ा शिकार बना। इससे जनता में व्यापक असंतोष पैदा हुआ। अनेक परिवारों ने सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट झेले, जिसकी पीड़ा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है।

हालांकि, मार्च 1977 के आम चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को भी साबित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और जनता ने मतदान के माध्यम से अपना फैसला सुनाया। पहली बार केंद्र में गैर–कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। यह लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण क्षण था।आपातकाल की समाप्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों से गहरा लगाव रखती है। सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जनता ही सर्वोच्च होती है। इस दौर ने संविधान निमार्ताओं की दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। आज,आपातकाल के पांच दशक बाद भी यह घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में याद की जाती है। इसका संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि नागरिक अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन से मजबूत होता है। आपातकाल का अंत भयावह अनुभवों और लोकतंत्र की पुनजार्गृति दोनों का प्रतीक था। यह इतिहास हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को सदैव सजग रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जागरूक नागरिक ही होते हैं।

आपातकाल के काले छींटे कब सुलझेंगे?

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसे आज भी काला अध्याय कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए थे। लगभग 21 महीने तक चले इस दौर में हजारों राजनीतिक कार्यकताओं को जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विरोध के हर स्वर को दबाने का प्रयास किया गया। आज, आपातकाल समाप्त हुए पाँच दशक के करीब समय बीत चुका है, लेकिन उसके काले छींटे पूरी तरह धुल नहीं पाए हैं। इसका कारण केवल इतिहास की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को लेकर लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां भी हैं। जब भी सत्ता के केंद्रीकरण, संस्थाओं की स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विपक्ष की भूमिका पर बहस होती है, तब आपातकाल की याद स्वतः ताजा हो जाती है। आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यह था कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष मीडिया और जागरूक नागरिकों से संचालित होता है। यदि इनमें से किसी भी स्तंभ को कमजोर किया जाता है तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए आपातकाल की घटनाओं का स्मरण केवल अतीत को कोसने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है।दुर्भाग्य से, आपातकाल पर राजनीतिक दल अक्सर अपने–अपने दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। एक पक्ष इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताता है, जबकि दूसरा पक्ष वर्तमान परिस्थितियों की तुलना उस दौर से करने का प्रयास करता है। इस राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप के बीच वास्तविक आवश्यकता यह है कि देश उस कालखंड का निष्पक्ष मूल्यांकन करे और उससे मिले सबकों को आत्मसात करे। आपातकाल के काले छींटे तभी पूरी तरह सुलझेंगे जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समाज और शासन दोनों की प्रतिबद्धता अटूट होगी। नागरिक अधिकारों का सम्मान, सत्ता की जवाबदेही, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती ही उस अंधकारमय दौर की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। इतिहास को भुलाना समाधान नहीं है; उससे सीख लेकर लोकतंत्र को और मजबूत बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि आपातकाल को केवल राजनीतिक विमर्श का विषय न बनाया जाए, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का स्थायी पाठ बनाया जाए। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होगा तथा शासन संविधान की मयार्दाओं के भीतर कार्य करेगा, तभी आपातकाल के वे काले छींटे वास्तव में मिट सकेंगे और भारत का लोकतंत्र और अधिक परिपक्व तथा सशक्त बन सकेगा।

(लेखक – सौरभ वार्ष्णेय)
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

लापरवाही की लपटों में जलती जिंदगी: कब जागेगा तंत्र?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग ने केवल एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि शासन–प्रशासन की संवेदनहीनता, नियामक संस्थाओं की निष्क्रियता और व्यवस्था की खोखली पड़ चुकी जवाबदेही को भी उजागर कर दिया है। इस दुर्घटना में कोचिंग सेंटर के अनेक विद्यार्थियों की असामयिक मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि उस सड़ी–गली व्यवस्था का परिणाम है, जो हर त्रासदी के बाद कुछ दिनों तक सक्रिय दिखती है और फिर गहरी नींद में सो जाती है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग, दिल्ली के शिशु अस्पताल में नवजातों की मौत, दिल्ली के होटल अग्निकांड, मुजफ्फरपुर अस्पताल की दुर्घटना और अब लखनऊ का अग्निकांड–इन घटनाओं की श्रृंखला बताती है कि भारत में मानव जीवन का मूल्य लगातार घटता जा रहा है। हर बार वही बयान सुनाई देता है–ह्यदोषियों को बख्शा नहीं जाएगाह्न, ह्यजांच के आदेश दे दिए गए हैंह्न, ह्यकड़ी कार्रवाई होगीह्न। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जांच और मुआवजा ही शासन का अंतिम दायित्व है? क्या सरकारें केवल दुर्घटना के बाद शोक व्यक्त करने और मुआवजा बांटने के लिए हैं? इन जहरीली काली आग ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक कालिख पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुँह पर।

लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी, वहां कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है कि क्या उस भवन को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त था? क्या भवन निर्माण मानकों का पालन किया गया था? क्या वहां आपातकालीन निकास मार्ग उपलब्ध थे? यदि थे, तो वे उपयोग में क्यों नहीं आए? और यदि नहीं थे, तो इतने लंबे समय तक प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? यह केवल भवन स्वामी की लापरवाही नहीं है। यदि कोई व्यावसायिक संस्थान नियमों की अनदेखी करते हुए वर्षों तक संचालित होता रहता है, तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र की मौन सहमति या भ्रष्ट गठजोड़ सक्रिय है। आखिर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? क्या उनका कार्य केवल लाइसेंस जारी करना और औपचारिक निरीक्षण करना भर रह गया है? या कमियों को ढंकते हुए अपनी जैबें गर्म करते रहना है?

वास्तविकता यह है कि देश के अधिकांश शहरों में सार्वजनिक सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऊंची–ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन उनमें सुरक्षा मानकों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहुमंजिला भवनों में अक्सर एक ही प्रवेश एवं निकास मार्ग होता है। अग्निशमन उपकरण या तो अनुपस्थित होते हैं या वर्षों से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। आपदा प्रबंधन की कोई नियमित मॉक ड्रिल नहीं होती। भवनों में क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाता है। नियम पुस्तकों में सुरक्षा व्यवस्था भले मौजूद हो, लेकिन जमीन पर उसकी स्थिति नगण्य है। इस विडम्बना का सबसे दुखद पक्ष यह है कि हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच समितियां गठित होती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन उन रिपोर्टों पर अमल नहीं होता। उपहार सिनेमा अग्निकांड से लेकर राजकोट और लखनऊ तक, देश ने अनेक त्रासदियों से सबक लेने की बात कही, परंतु व्यवस्था ने कुछ नहीं सीखा। प्रशासन की स्मृति अत्यंत अल्पकालिक हो चुकी है। कुछ दिनों तक छापेमारी, निरीक्षण और नोटिस जारी करने का नाटक चलता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।

यह स्थिति केवल प्रशासनिक अक्षमता की नहीं, बल्कि नैतिक पतन की भी है। भ्रष्टाचार ने सुरक्षा व्यवस्था की आत्मा को खोखला कर दिया है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर आंखें मूंद लेते हैं। भवन स्वामी अधिक लाभ कमाने के लिए सुरक्षा उपायों की उपेक्षा करते हैं। परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवाते हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे शहरों का विकास मानव–केंद्रित है? हम स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी और विश्वस्तरीय शहरों के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन यदि नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे विकास का क्या अर्थ है? किसी भी सभ्य समाज की पहली पहचान उसके नागरिकों की सुरक्षा होती है। यदि एक कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल या मॉल भी सुरक्षित नहीं है, तो हमें अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करना होगा। आज आवश्यकता केवल दोष निर्धारण की नहीं, बल्कि व्यापक संरचनात्मक सुधारों की है। सबसे पहले देशभर में सभी व्यावसायिक भवनों, कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, मॉल, होटल और सार्वजनिक स्थलों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए। जिन संस्थानों के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं या जो मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

दूसरे, अग्निशमन विभाग को आधुनिक संसाधनों और पर्याप्त मानवबल से सुसज्जित करना होगा। अनेक रिपोर्टों के अनुसार देश में फायर स्टेशनों और प्रशिक्षित फायर कर्मियों की भारी कमी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के अनुरूप अग्निशमन सेवाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। तीसरे, प्रत्येक सार्वजनिक भवन में हर छह माह में अनिवार्य मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आपात स्थिति में लोग घबराने के बजाय संयमपूर्वक अपनी सुरक्षा कर सकें। चौथे, जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। केवल भवन स्वामी ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों के उन अधिकारियों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने लापरवाही बरती या नियमों की अनदेखी की। जब तक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाए जाएंगे, तब तक सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन की प्राथमिकता ह्यदुर्घटना के बाद की प्रतिक्रियाह्न से बदलकर ह्यदुर्घटना से पूर्व की रोकथामह्न पर केंद्रित होनी चाहिए। सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना भी है। प्रशासन की सफलता मुआवजा राशि में नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने की क्षमता में निहित होती है।

कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, कारखाने, होटल आदि के मिस मैनेजमेंट और लापरवाही का स्थानीय प्रशासन को अंदाजा होना चाहिए कि उसके कार्यक्षेत्र में किस तरह के व्यवसाय कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए चलाए जा रहे हैं? प्रश्न है कि इन बढ़ती दुर्घटनाओं की नृशंस चुनौतियों का क्या अंत है? बहुत कठिन है दुर्घटनाओं की उफनती नदी में जीवनरूपी नौका को सही दिशा में ले चलना और मुकाम तक पहुंचाना, यह चुनौती सरकार के सम्मुख तो है ही, आम जनता भी इससे बच नहीं सकती। मनुष्य अपने स्वार्थ और रुपए के लिए इस सीमा तक बेईमान और बदमाश हो जाता है कि हजारों के जीवन और सुरक्षा से खेलता है। दो–चार परिवारों की सुख समृद्धि के लिए अनेक घर–परिवार उजाड़ देता है। तंत्र की काहिली और आपराधिक लापरवाही के चलत ऐसे हादसे होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे–कानूनों का उल्लंघन होता है। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती है? सारे कानून कायदों का वहीं पर स्याह हनन होता है।

जैसे–जैसे जीवन तेज होता जा रहा है, सुरक्षा उतनी ही कम हो रही है, जैसे–जैसे प्रशासनिक सर्तकता की बात सुनाई देती है, वैसे–वैसे प्रशासनिक कोताही के सबूत सामने आते हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हर बड़ी दुर्घटना कुछ शोर–शराबें के बाद एक और नई दुर्घटना की बाट जोहने लगती है। सरकार और सरकारी विभाग जितनी तत्परता मुआवजा देने में और जांच समिति बनाने में दिखाते हैं, अगर सुरक्षा प्रबंधों में इतनी तत्परता दिखाएं तो दुर्घटनाओं की संख्या घट सकती है। लखनऊ का यह अग्निकांड एक चेतावनी है। यदि अब भी शासन–प्रशासन नहीं जागा, तो ऐसी त्रासदियां भविष्य में और अधिक भयावह रूप धारण कर सकती हैं। यह समय आत्ममंथन का है, क्योंकि हर अग्निकांड के बाद यदि केवल राख बचती है और व्यवस्था फिर उसी ढर्रे पर लौट जाती है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि एक प्रकार का संस्थागत अपराध है। देश को अब संवेदना नहीं–व्यवस्था चाहिए, जांच नहीं–जवाबदेही चाहिए और आश्वासन नहीं–ठोस कार्रवाई चाहिए। अन्यथा हर अग्निकांड के बाद यही प्रश्न गूंजता रहेगा–आखिर कब जागेगा तंत्र?

(लेखक – ललित गर्ग)
(लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

बाल कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण का दिया सशक्त संदेश

नई दिल्ली, वेब वार्ता। सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, चाणक्यपुरी में आयोजित समर कैम्प मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित डांस-ड्रामा एवं नृत्य-नाटिका प्रकृति बोलती है की प्रभावशाली प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया।

मात्र 14 दिनों की ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में तैयार इस एक घंटे के कार्यक्रम में बच्चों ने अभिनय, नृत्य और अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों की माताओं ने भी आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया।

शो की कोरियोग्राफी और निर्देशन स्पेस परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक एवं प्रसिद्ध कोरियोग्राफर राजा आनंद ने किया। नन्हे कलाकारों ने प्रकृति की पीड़ा, उसकी चेतावनी और संरक्षण की आवश्यकता को मंच पर जीवंत कर दर्शकों को भावुक कर दिया।

दिल्ली सरकार भी महिलाओं से किया वादा पूरा करे : अरुण तोमर

नई दिल्ली, वेब वार्ता। आम आदमी पार्टी के घोंडा विधानसभा से पूर्व संगठन मंत्री अरुण तोमर ने कहा है कि पंजाब सरकार ने महिलाओं से किया अपना प्रमुख चुनावी वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार से भी महिलाओं के हित में किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने की मांग की।

अरुण तोमर ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता से जो वादे करती है, उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने बताया कि पंजाब में सामान्य और अन्य श्रेणियों की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्र परिवार की प्रत्येक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा।

तोमर ने बताया कि 1 जुलाई को महिलाओं के खातों में तीन माह की सहायता राशि एक साथ भेजी जाएगी। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4500 रुपये प्राप्त होंगे।

मानसून को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियां अधूरी

नई दिल्ली, वेब वार्ता। डॉ. नरेश कुमार ने दिल्ली सरकार की मानसून तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के दावे बड़े हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तैयारियां अधूरी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है।

डॉ. नरेश कुमार ने कहा कि पिछले वर्षों में पहली ही बारिश में राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली सरकार को सभी संबंधित एजेंसियों और राजनीतिक दलों के साथ संयुक्त बैठक कर मानसून के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, ताकि दिल्लीवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

डॉ. नरेश कुमार ने दावा किया कि फ्लड विभाग के अनेक नालों की सफाई का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने नालों से निकाली गई गाद के निस्तारण और उसके स्वतंत्र परीक्षण की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने कहा कि यमुना तटवर्ती क्षेत्रों, अनधिकृत कॉलोनियों तथा ग्रामीण इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए सरकार को पेयजल, सुरक्षित निकासी और चिकित्सीय सुविधाओं की स्पष्ट योजना सार्वजनिक करनी चाहिए।

उपराज्यपाल ने अपराध पर सख्त नियंत्रण रखने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और कामकाज व कल्याण से जुड़ी मुख्य प्राथमिकताओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस बल को अपराध पर सख्त नियंत्रण रखने का निर्देश देते हुए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

अधिकारियों को लगातार कौशल बढ़ाने, पुलिसिंग के बेहतरीन तरीके अपनाने, एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करने और कम्युनिटी पुलिसिंग व जानकारी जुटाने में आरडब्लूए और मार्केट एसोसिएशन को सक्रिय रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की।

उपराज्यपाल ने ट्रैफिक नियमों को सख्त से लागू करके ट्रैफिक की चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया, खासकर गलत दिशा में गाड़ी चलाने और ज्यादा जाम वाली जगहों पर साथ ही सड़क का इस्तेमाल करने वालों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण, बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पुलिस रिहायशी परिसरों को 'जोरो-वेस्ट' कॉलोनियों में बदलने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि सशक्तिकरण के साथ-साथ जवाबदेही और सार्थक परिणाम भी होने चाहिए। पूरे पुलिस बल को अपना पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया, क्योंकि वे नए संकल्प के साथ काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली का हर निवासी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर सेवा का अनुभव कर सके।

सामुदायिक सेवा से सशक्त समाज का संदेश

नई दिल्ली,वेब वार्ता

गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जी.टी. रोड, शाहदरा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के दस दिवसीय विशेष शिविर के छठे दिन सामुदायिक सेवा दिवस उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर सेवा भावना का परिचय दिया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रजी अहमद के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी गजेंद्र कौशिक की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में इकबाल अहमद अमीन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज सेवा, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता के महत्व से अवगत कराया।

इस अवसर पर अनुज कुमार गोयल, हर्ष कुमार शर्मा, मनोज कुमार सिंह तथा प्रदीप कुमार सहित विद्यालय के अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। स्वयंसेवक श्याम मोगा, लक्ष्य वर्मा और शिवम रजत ने सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाई। शिविर के अंतर्गत 17 जून से 26 जून तक स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और व्यक्तित्व विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण

जांच समिति पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, वेब वार्ता

राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की वैधता पर सवाल खड़े करते हुए उसे फर्जी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए गठित की गई यह जांच समिति केवल मामले को दबाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक माध्यम मंच पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि कानून के तहत बिना प्राथमिकी दर्ज किए किसी विशेष जांच दल का गठन नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूछा कि आखिर किस कानून और किस धारा के अंतर्गत इस जांच दल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जांच दल के पास किसी व्यक्ति को समन भेजने, गिरफ्तारी करने अथवा छापेमारी करने जैसी कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में यह जांच दल प्रभावी जांच करने में सक्षम नहीं है।

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह जांच समिति केवल लीपापोती करने और मामले को रफा-दफा करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने वर्ष 2021 में अयोध्या भूमि खरीद प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल का भी उल्लेख किया और दावा किया कि उस मामले में भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तथा आज तक जांच का कोई स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में भी छोटे कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि यदि लंबे समय से चढ़ावे में अनियमितताएं हो रही थीं तो इसमें बड़े स्तर पर संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि यदि सरकार की मंशा वास्तविक दोषियों तक पहुंचने की है, तो अब तक मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को क्यों नहीं सौंपी गई है। उन्होंने पूछा कि अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। हालांकि, संबंधित पक्षों की ओर से अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच इस मुद्दे पर आगे भी विवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

12 वर्षों में काम हुए होते तो घर-घर बताने की जरूरत नहीं पड़ती : संजीव शर्मा

नई दिल्ली, वेब वार्ता। रोहताश नगर विधानसभा प्रभारी एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव संजीव शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पिछले 12 वर्षों में जनता के हित में वास्तविक विकास कार्य हुए होते तो आज पार्टी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संजीव शर्मा ने कहा कि जब जनता समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछती है तो उनके पास जवाब नहीं होता।

समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था से जनता को होगा लाभ

नई दिल्ली, वेब वार्ता। भाजपा शाहदरा जिला महामंत्री रोमेश चंद गुप्ता ने दिल्ली सरकार की नई समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों और कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा तथा विभिन्न सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

रोमेश चंद गुप्ता ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अनुमति, अनुज्ञापत्र, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे, जिससे अनावश्यक विलंब की समस्या कम होगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत चलचित्र की शूटिंग की अनुमति 15 दिनों में, मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा होटल पंजीकरण और संचालन अनुमति 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बिजली कनेक्शन, तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण और खाद्य व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अनुमतियों की प्रक्रिया भी निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएगी। रोमेश चंद गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है।

झुग्गीवासियों को लेकर भाजपा की नीति और नियत में विरोधाभास: देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली, वेब वार्ता

लोगों को विस्थापित किया जा चुका है

देवेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि गरीबों के हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश जारी कर योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में लगभग 20 लाख लोग निवास करते हैं और पिछले 15 महीनों में बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया जा चुका है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीति और नियत में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर झुग्गी बस्तियों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को वहीं मकान देने की घोषणाएं कर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि जहां झुग्गी, वहीं मकान की अवधारणा कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने शुरू की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें 1 जनवरी 2025 तक की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 5 लाख परिवारों को बहुमंजिला इमारतों में आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार वास्तव में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के प्रति गंभीर है, तो सत्ता में आने के बाद पिछले 15 महीनों के दौरान दिल्ली की दो दर्जन से अधिक झुग्गी बस्तियों को क्यों उजाड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में सुभाष नगर, रेसकोर्स और कालिंदी कुंज क्षेत्र की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन प्रभावित लोगों को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया। देवेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी से यह भी पूछा कि कांग्रेस शासनकाल में शुरू किए गए कालकाजी विस्तार, गोविंदपुरी, कठपुतली कॉलोनी और वजीरपुर स्थित जेलरवाला बाग आवास परियोजनाएं अब तक पूरी क्यों नहीं हो सकीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत नरेला, बवाना और घेवरा में बनाए गए लगभग 45 हजार फ्लैट आज भी गरीबों को आवंटित नहीं किए गए और वे खंडहर में तब्दील हो चुके हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की अवसरवादी राजनीति और भाजपा की प्रतिशोधात्मक नीति के कारण हजारों गरीबों के लिए बनाए जा रहे आवासीय परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कालकाजी और वजीरपुर में प्रधानमंत्री द्वारा प्रतीकात्मक रूप से चाबियां सौंपने के बावजूद आज तक परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं।

उन्होंने मांग की कि दिल्ली सरकार ओ जोन की कॉलोनियों को नियमित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करे कि जब तक विस्थापित लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उन्हें हटाया न जाए। इसके लिए सरकार को तत्काल अध्यादेश जारी करना चाहिए।

देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि झुग्गी बस्तियों, पुनर्वास कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के नाम पर जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने अपने शासनकाल में लोगों को भ्रमित किया, उसी राह पर अब भाजपा सरकार भी चल रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी वैधानिक प्रावधान के जेजे क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी करने और पीपीपी मॉडल के तहत नई योजनाओं की घोषणाएं भी भाजपा के चुनावी वादों की तरह साबित होंगी। उन्होंने महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने के वादे का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अब तक उसे भी पूरा नहीं कर सकी है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मोती नगर में गाद निकालने के काम का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को मोती नगर में गाद निकालने (डीसिल्टिंग) के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक हरीश खुराना और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मॉनसून से पहले हमारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी और चीफ इंजीनियर पूरी दिल्ली में सड़कों पर बने पीडब्ल्यूडी के स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (बारिश का पानी निकालने वाले नालों) से गाद निकालने के काम की निगरानी कर रहे हैं। हमारे पास दो साल के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जब तक हम खुद मौके पर जाकर काम का निरीक्षण नहीं करते, तब तक हमें असल स्थिति का पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि आज कीर्ति नगर और मोती नगर के दौरे के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए कि सभी काम समय पर और बेहतरीन स्टैंडर्ड के साथ पूरे किए जाएं।

विधायक हरीश खुराना ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि आज मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कीर्ति नगर स्थित सतगुरु रामदास मार्ग का मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान क्षेत्र में जलभराव की समस्या, सड़कों की वर्तमान स्थिति, जल निकासी व्यवस्था तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े विषयों का विस्तृत जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के स्थायी एवं समयबद्ध समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

विधायक हरीश खुराना ने कहा कि क्षेत्रवासियों की सुविधा, सुचारु आवागमन और बेहतर आधारभूत संरचना सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। जनसमस्याओं के समाधान और मोती नगर विधानसभा के समग्र विकास के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।

भाजपा ने अपने कार्यकाल में जनहित के लिए कोई ठोस काम नहीं किया : हाजी जरीफ

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव तथा कबीर नगर वार्ड से निगम पार्षद हाजी जरीफ ने भारतीय जनता पार्टी के विशेष जनसंपर्क अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भाजपा ने अपने शासनकाल में जनता के हित में वास्तविक कार्य किए होते तो उसे घर-घर जाकर अपनी उपलब्धियां बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

हाजी जरीफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे तीन दिवसीय विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी नागरिकों से संपर्क कर केंद्र और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश को बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक चुनौतियों जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए। हाजी जरीफ ने कहा कि भाजपा सरकार यह दावा कर रही है कि यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा यमुना पुनर्जीवन और स्वच्छता सुविधाओं के

लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने पूछा कि इन परियोजनाओं का कार्य अब तक कितना पूरा हुआ है और भाजपा शासनकाल के दौरान यमुना के जल की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है। जलभराव की समस्या को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। हाजी जरीफ ने कहा कि सरकार द्वारा नालों की सफाई और गाद निकालने के बड़े दावे किए जा रहे हैं। यदि वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य हुआ है तो राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष जलभराव की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि अधिकांश योजनाएं अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में देश ने आर्थिक कठिनाइयों, हिंसा और सामाजिक तनाव का सामना किया है तथा गरीबों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है।

हाजी जरीफ ने कहा कि भाजपा को जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय लोगों से यह पूछना चाहिए कि उन्हें शासनकाल के दौरान वास्तविक रूप से क्या सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने पर भाजपा को जनता की वास्तविक भावना का पता चल जाएगा।

जल बोर्ड की लापरवाही से शकरपुर के लोग परेशान : शरद दीक्षित

नई दिल्ली, वेब वार्ता। लोगों की आवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता शरद दीक्षित ने शकरपुर क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पानी के बिलों में त्रुटियों के कारण स्थानीय उपभोक्ता पिछले कई महीनों से परेशान हैं।

शरद दीक्षित ने कहा कि क्षेत्र के अनेक उपभोक्ता अपने पानी के बिलों में सुधार कराने के लिए लगातार जल बोर्ड कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में मीटर सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद बिलों में उन्हें बंद या खराब दर्शाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद निरीक्षण और बिल सुधार की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। इस संबंध में उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी है। शरद दीक्षित ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता का मीटर सही स्थिति में है, तो उसे गलत बिल देना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से लंबित मामलों की शीघ्र समीक्षा कर प्रभावित लोगों को राहत देने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

संक्षिप्त वार्ता

चार घंटे तक कार में बंद रहा मासूम, दम घुटने से दर्दनाक मौत

वेब वार्ता, कुशीनगर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में दरवाजे पर खड़ी कार में खेलना पांच वर्ष के अनस के लिए जानलेवा साबित हुआ।खेलते-खेलते कार का दरवाजा लाक हो गया। जिससे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। गुलेलहा गांव में मंगलवार को हुई इस घटना के बाद कोहराम मच गया। स्वजन द्वारा पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने पर शव को दफना दिया गया। गुलेलहा के रहने वाले मजनू का पुत्र अनस सुबह करीब 11 बजे घर के सामने खड़ी कार का दरवाजा खोल कर उसमें बैठ गया और खेलने लगा। इसी दौरान कार का दरवाजा लाक हो गया। बातचीत व कार्य में व्यस्त परिजन ध्यान नहीं दे पाए।

लगभग चार घंटे तक बच्चे के दिखाई न देने पर उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आशंका होने पर कार का दरवाजा खोला गया, तो अनस अचेत मिला। परिजन उसे लेकर मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचे, वहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम न होने से मृत्यु का कारण तो स्पष्ट नहीं हो सका। लेकिन माना जा रहा कि दम घुटने से बच्चे की मृत्यु हुई है।

आईएमएस-बीएचयू में इंक्रीमेंट विवाद गहराया, नर्सिंग अधिकारियों को नियम विरुद्ध लाभ देने के आरोप

वाराणसी/वेब वार्ता

आईएमएस-बीएचयू में आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब नर्सिंग अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त इंक्रीमेंट का मामला भी चर्चा में आ गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भर्ती नियमों और निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए कई नर्सिंग अधिकारियों को अतिरिक्त नॉन-एब्जॉर्बेबल इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान किया गया। मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायत में कहा गया है कि बीएचयू में वर्ष 2005 से स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए बीएससी नर्सिंग योग्यता अनिवार्य की गई थी। नियमानुसार किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में ही सीमित संख्या में अतिरिक्त नॉन-एब्जॉर्बेबल इंक्रीमेंट दिए जा सकते हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में इन नियमों का पालन किए बिना ही अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान किया गया, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही पड़ताल के दौरान इस मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया और सेवा लाभों से संबंधित निर्णयों की समीक्षा की जा रही है। जांच एजेंसियों ने विभिन्न स्तरों पर संबंधित लोगों से पूछताछ कर दस्तावेजों और प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी जुटाई है। मामले से जुड़े सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की गई है। कुछ पूर्व और वर्तमान अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि जांच एजेंसियों या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आईएमएस-बीएचयू में कार्यरत 700 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों में बड़ी संख्या राजस्थान के विभिन्न संस्थानों से आई है। भर्ती प्रक्रिया और सेवा लाभों को लेकर पूर्व में भी शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियों की सक्रियता के कारण मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

जिला पंचायत सदस्य ने अध्यक्ष व उनके पुत्र पर लगाए गंभीर आरोप

ललितपुर। जाखलौन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य अमर विश्वकर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर क्षेत्र के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने, जमीनी मामलों में अनियमितता बरतने तथा जिला पंचायत कार्यालय में बुलाकर अभद्रता, मारपीट और जान से मारने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच कराकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को तुवन चौराहा स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत सदस्य अमर विश्वकर्मा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 जून को जिला पंचायत अध्यक्ष के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा उन्हें फोन कर जिला पंचायत कार्यालय बुलाया गया था। कार्यालय पहुंचने पर उन्हें अध्यक्ष कक्ष में आने के लिए कहा गया। अमर विश्वकर्मा का आरोप है कि जब उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लंबित होने और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात रखी, तो जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अपशब्द कहे।

सड़क पर दौड़ेंगे जागरूकता संदेश

यात्री वाहनों और बसों पर अब अनिवार्य होगा पशुओं पर दया करो का स्लोगन

हरी शंकर शर्मा, वेब वार्ता

कानपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा संवेदानात्मक बदलाव होने जा रहा है। अब सभी यात्री वाहनों और रोडवेज बसों पर ह्लपशुओं पर दया करोह्व जैसे जीव-जंतु संरक्षण से जुड़े जागरूकता संदेश लिखे नजर आएंगे। कानपुर आरटीओ विभाग ने इस आदेश का जमीनी स्तर पर पालन शुरू करा दिया है।

मोटयान निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि परिवहन आयुक्त का निर्देश दो से तीन माह पूर्व ही आ गया था,लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने में कुछ समय लग गया। अब यह निर्देश पूरी तरह से अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मूल उद्देश्य आम जनता में बेजुबान पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और जीव-जंतुओं के संरक्षण का संदेश हर नागरिक तक पहुँचाना है। यह स्लोग कमार्शियल वाहनो पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के साथ ही स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वाहन पर लिखे संदेश को दूर से भी स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके, इसके लिए स्लोगन के अक्षरों की न्यूनतम ऊंचाई 150 मिलीमीटर (एमएम) तय की गई है। आरटीओ प्रशसन के अनुसार, सार्वजनिक वाहनों के माध्यम से यह संदेश बहुत तेजी से समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचेगा। इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए वाहनों की चेकिंग के दौरान भी इसकी समीक्षा की जाएगी।

फिटनेस सेंटरो पर भी इसका हो रहा है पालन

आरआई संतोष कुमार ने बताया कि ह्लपशुओं पर दया करोह्व का स्लोगन एटीएस फिटनेस सेंटरो पर आने वाले वाहनो में लिखवाने व स्टिकर लगवाने का कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। इस स्लोगन से बेजुबान पशुओ के अस्तित्व को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभायेगा। हांलकि वाहन स्वामी भी इस नेक काम में अपनी भागीदारी निभाने में लगे हुए है।

आरटीओ प्रशसन के अनुसार, सार्वजनिक वाहनों के माध्यम से यह संदेश बहुत तेजी से समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचेगा। इस आदेश

लखनऊ हादसे के बाद हरदोई में चला सुरक्षा का चाबुक

लक्ष्मीकान्त पाठक/हरदोई। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद हरदोई प्रशासन हरकत में आ गया है। बुधवार को शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई। इस दौरान कई स्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और भवन उपविधियों का उल्लंघन सामने आने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लाइब्रेरी और एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया, जबकि एक होटल का बिजली कनेक्शन काटकर उसके संचालन पर रोक लगा दी गई।

गंगा में नॉनवेज पार्टी मामले के पांचों आरोपितों को मिली जमानत, कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश

वाराणसी/वेब वार्ता

मां गंगा में नाव पर नॉनवेज पार्टी करने और शराब सेवन के वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपितों को अदालत से राहत मिल गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय की अदालत ने सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपये की दो-दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में आरोपितों की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

मामला तब चर्चा में आया जब बीते सोमवार देर शाम गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज पार्टी और शराब सेवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की सर्विलांस टीम ने वीडियो की जांच शुरू की और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की।

पांच लोगों को किया गया था गिरफ्तार

जांच के बाद पुलिस ने सूजाबाद पड़ाव निवासी दीपक कुमार, नाव चालक अजय साहनी, डोमरी निवासी अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जिस नाव पर पार्टी किए जाने का वीडियो सामने आया था, उसे भी सीज कर दिया था।

जांच में छह माह पुराना निकला वीडियो

सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार जांच में पता चला कि मान मंदिर घाट के पास बनाया गया यह वीडियो करीब छह माह पुराना है। हालांकि वीडियो के सार्वजनिक होने और धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद को देखते हुए पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। गंगा में नाव पर पार्टी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 16 मार्च को भी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस मामले में कोतवाली पुलिस ने 17 मार्च को 14 युवकों को गिरफ्तार किया था। बाद में उस प्रकरण में आरोपितों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। वहीं अदालत से जमानत मिलने के बाद पांचों आरोपितों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस घटना ने एक बार फिर गंगा नदी और घाटों की मयार्दा बनाए रखने को लेकर बहस को तेज कर दिया है।

रास्ता बंद होने से परेशान पीड़ित ने आत्महत्या की दी चेतावनी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कोतवाली बैनीगंज क्षेत्र के ग्राम बरगदिया मजरा झरोईया में निकास मार्ग अवरुद्ध किए जाने के मामले में एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते-लगाते परेशान हो गया है। पीड़ित बाबूराम पुत्र जालिम ने आरोप लगाया है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उनका परिवार गंभीर परेशानियों का सामना कर रहा है।

बाबूराम के अनुसार गांव के अशोक कुमार, रामसागर पुत्रगण शंकर रैदास, शांति पत्नी शंकर रैदास तथा रोशनी पत्नी अशोक कुमार उनके मकान के निकास मार्ग पर लकड़ी, छप्पर एवं अन्य सामान रखकर रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली-गलौज और झगड़ा करने की बात भी उन्होंने कही है।

पीड़ित का आरोप है कि 23 जून की रात करीब 8 बजे विपक्षी उनके घर के बाहर पहुंचे और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हंगामा करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से चले गए।

बाबूराम ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस चौकी प्रतापनगर एवं कोतवाली बैनीगंज में कई बार की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि परिवार लगातार भय और तनाव के माहौल में जीवन यापन कर रहा है तथा पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विपक्षी आए दिन मारपीट, धमकी और अभद्र व्यवहार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है।

बाबूराम ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रास्ता खुलवाकर न्याय नहीं दिलाया गया तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को विवश हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।

पचदेवरा पुलिस ने चोरी का किया खुलासा

चार आरोपी गिरफ्तार, जेवरात व गैस सिलेंडर बरामद

हरदोई, 24 जून। थाना पचदेवरा पुलिस ने घर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी गए आभूषण, नकदी तथा गैस सिलेंडर बरामद किया है। मामले में दो बाल अपचारियों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार 22 जून 2026 को ग्राम उमरिया कला निवासी रजनीश कुमार पुत्र बाबूराम ने थाना पचदेवरा में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोर उनके घर से आभूषण और गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए हैं। शिकायत के आधार पर थाना पचदेवरा में मुकदमा संख्या 131/2026 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल सौरभ पुत्र शिवरतन, आलोक पुत्र आदेश, जगेश पुत्र राधेश्याम निवासीगण ग्राम उमरिया कला तथा मनोज पुत्र रामदास निवासी ग्राम बीरपुर, थाना पचदेवरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दो बाल अपचारियों को भी अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मंगलसूत्र, एक मेहंदी मंगलसूत्र, एक जोड़ी झाले, नाक की कील, 500 रुपये नकद तथा एक गैस सिलेंडर बरामद किया है। बरामद सामान चोरी की घटना से संबंधित बताया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चोरी की घटना के खुलासे और बरामदगी में थाना पचदेवरा पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनायेंगे ब्रजेश पाठक

लखनऊ (वेब वार्ता)। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में अनेक मासूम बच्चों की असामयिक मृत्यु के शोक के कारण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल 25 जून को अपना जन्मदिन नहीं मनायेंगे। इसकी जानकारी ब्रजेश पाठक ने स्वयं अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी है। उप मुख्यमंत्री ने लिखा कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने मन को भीतर तक उद्वेलित और व्यथित कर दिया है। इस दु :खद घटना में अनेक मासूम बच्चों की असामयिक मृत्यु ने पूरे प्रदेश को शोक और पीड़ा से भर दिया है।

उन्होंने लिखा जब कई परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए हों, तब अपने जन्मदिन का उत्सव मनाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी गहन संवेदना और शोक के भाव के साथ मैंने निर्णय लिया है कि कल, 25 जून को, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊँगा। यह दिन उन दिवंगत मासूम बच्चों की पावन स्मृति तथा उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना को समर्पित रहेगा।

अधिवक्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट, कई नामजद समेत 60-70 पर मुकदमा

वाराणसी/वेब वार्ता

भेलूपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर इलाके में अधिवक्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पीड़ित अधिवक्ता की शिकायत पर भेलूपुर पुलिस ने कई नामजद आरोपियों समेत 60 से 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है।

रानीपुर निवासी अधिवक्ता विशाल नारायण सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने पहले घर का ताला तोड़ा और जबरन अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने घर में जमकर तोड़फोड़ की और ईंट-पत्थर चलाते हुए उत्पात मचाया। विरोध करने पर घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई।

पूर्व विधायक पंडित रामकुमार तिवारी की सातवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

ललितपुर। महरौनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित रामकुमार तिवारी की सातवीं पुण्यतिथि पर बुधवार को बड़ोनिया मैरिज गार्डन में श्रद्धांजलि सभा एवं स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

कार्यक्रम का आयोजन उनके पुत्र निखिल तिवारी द्वारा किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकताओं, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर स्वर्गीय तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

पंडित रामकुमार तिवारी महरौनी क्षेत्र की राजनीति के एक सम्मानित और लोकप्रिय जननेता रहे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर वर्ष 2007 में महरौनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर वर्ष 2007 से 2012 तक विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के विकास, ग्रामीण अंचलों की समस्याओं के समाधान, सड़क, शिक्षा, सिंचाई एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनकी सरलता, मिलनसार स्वभाव और जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण वे जनता के बीच विशेष पहचान रखते थे। सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए कहा कि पंडित रामकुमार तिवारी ने राजनीति को सेवा और जनकल्याण का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने कार्यों से क्षेत्र में विकास की नई पहचान स्थापित की और हमेशा आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखा।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके पुत्र निखिल तिवारी ने कहा कि उनके पिता के आदर्श, संघर्ष और जनसेवा की भावना आज भी समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया।

श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने स्वर्गीय पंडित रामकुमार तिवारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम का वातावरण श्रद्धा, सम्मान और भावनात्मक स्मृतियों से ओत-प्रोत रहा।

राम मंदिर चढ़ावा में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में दानराशि एवं चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले और चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी, हरदोई के संयुक्त तत्वावधान में धरना-प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की।

धरना-प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दानराशि एवं चढ़ावे से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने तथा कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। ऐसे में यदि मंदिर की दानराशि और चढ़ावे में किसी प्रकार की

अनियमितता हुई है तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है। श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने के लिए जांच की प्रगति और निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना भी आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जाए।

कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन सिंह, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हसन अहमद, शहर कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष उमा राजवंशी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजीत विशाल नंदवंशी, जिला उपाध्यक्ष भुट्टो मियां, एससी-एसटी विभाग के जिला अध्यक्ष विनीत वर्मा, पीसीसी सदस्य आशीष पाल, पीसीसी सदस्य अमरेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव शिव पाल, ब्लॉक अध्यक्ष शशिकांत तिवारी, शरीफ अहमद, चांद मोहम्मद, वसीम अहमद, जान मोहम्मद, इस्लाम गाजी, रवींद्र वर्मा, विनोद यादव, एजाज भाई उर्फ बबन, तुषार दीक्षित, कोमल सिंह, सोनम यादव, विमलेश कुमार, संध्या वर्मा, अजय दीक्षित, दीपक कुमार वर्मा, बादाम सिंह यादव, एडवोकेट सोम सैनी, एडवोकेट राम बहरे, मंजू रहमत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर की दानराशि से जुड़े कथित प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

पहली ही बारिश में बिगड़ी मुंबई की हालत

सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक पानी में डूबे; 24 ट्रेनें कैंसिल, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है

मुंबई। मानसून की पहली बारिश में ही खराब हो गई है. बारिश से मुंबई में आफत खड़ी हो गई है. सड़कों से लेकर अडंरपास, सबवे और रेलवे ट्रैकों तक पानी से लबालब भरे हुए हैं. शहर के विभिन्न हिस्सों में जन-जीवन बुरी तरह से बर्बाद हो गया है.

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए मुंबई में भारी बारिश का अनुमान जताया है और येलो अलर्ट जारी किया है. मुंबई के साथ-साथ पूरे राज्य में बारिश का मौसम बने रहने की संभावना है, जिस वजह से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

'नहीं ढूंढ़ पाए समस्या का अस्थाई समाधान'

अंधेरी अंडरपास की स्थिति के बारे में बात करते हुए बीएमसी नगर निगम के अधिकारी ऋतिक ने कहा कि हम पानी भरने की इस गंभीर समस्या का कोई अस्थाई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं. हमारे अधिकारी ये सुनिसश्चित करने के लिए यहां तैनात रहते हैं कि गाड़ियों यहां से न गुजरें. लेकिन कुछ रिक्शा फिर भी अपनी गाड़ियों को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं. एक रिक्शा पानी में फंस भी गया था. ड्राइवर की जान खतरे में थी. हमारे दो अधिकारियों ने उसे बाहर निकालने में मदद की.

रेल सेवा जारी रही

बीएमसी ने कहा कि पानी से भरे अंधेरी अंडरपास को छोड़कर सभी सब-वे चालू रहे हैं. जबकि शहर भर में रेल सेवा सामान्य रूप से चलती रही है. जोरदार बारिश के बाद भी वेस्टर्न रेलवे ने पुष्टि की कि सुबह व्यस्त वक्त में हार्बर लाइन और चर्चगेट सहित मुख्य रूट्स पर सबअर्बन ट्रेनें नॉर्मल रूप से चलती रहीं. हालांकि, रातभर हुई बारिश की वजह से मुंबई और नवी मुंबई के विभिन्न हिस्सों में जलभराव भर गया है.

मुंबई में कितनी बारिश हुई?

बीएमसी के बारिश के आंकड़ों के अनुसार, 23 जून को सुबह 8:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच शहर में औसतन 56 एमएम बारिश हुई. वहीं, पूर्वी उपनगरों में 23 एमएम और पश्चिमी उपनगरों में 33 एमएम बारिश दर्ज हुई है. रात 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच, पश्चिमी उपनगरों में विभिन्न जगहों पर अच्छी-खासी बारिश हुई.

जलभराव से रोजमर्रा की जिंदगी बाधित

मंगलवार तक हुई भारी बारिश ने मुंबई के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है. सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया और सिविल अधिकारियों द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवाजाही पर रोक लगाने के कारण यात्रियों को ट्रैफिक में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. एवरार्ड नगर में सबवे पानी से भर गया है. आम लोगों के लिए इसे बंद कर दिया गया है. साकी नाका मेट्रो स्टेशन इलाके सहित शहर के विभिन्न इलाकों की तस्वीरों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है.

ईरान घुटने टेकने को तैयार...

शांति समझौते के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने किया चौंकाने वाला दावा

अमेरिका। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर चल रही उठापटक के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान हारने की कगार पर है। वह कुछ भी देने को राजी हो गया है।

अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता को पूरा करने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। स्विट्जरलैंड की बातचीत के बाद ईरान की फ्रीज हुई संपति और बैन हटना शुरू हो गए हैं। हालांकि परमाणु और होर्मुज को लेकर दोनों देशों में स्पष्ट स्थिति नहीं बन पा रही है। इसकी वजह से शांति समझौते के टूटने का खतरा मंडराता रहता है। एक तरफ मामला शांति होता तो दूसरी राष्ट्रपति ट्रंप या ईरान फिर कोई विवादित बयानबाजी कर देते हैं। एक बार फिर ट्रंप ने विवादित दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान बिल्कुल हारने की कगार पर है, घुटने टेकने को तैयार है, हमें लगभग कुछ भी देने को राजी है, और दशकों में पहली बार, अमेरिका और उसके राष्ट्रपति यानी मुझे का बहुत ज्यादा सम्मान कर रहा है।

अमेरिका में पास प्रस्ताव पर भी जताई आपत्ति

और ऐसे में वर सीनेट ने 'वॉर पावर्स एक्ट' पर एक ऐसे समय में बेकार वोटिंग करने का फैसला किया जिसका कोई मतलब नहीं है। इससे दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले देश को यह संदेश गया कि अमेरिका को मेरा उनके खिलाफ किया जा रहा काम पसंद नहीं है और मुझे इसे रोकना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद ही की है। चार रिपब्लिकन 'लूजर्स' (हारने वालों) ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा, इस सबका क्या मतलब है? इन सीनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे किसी न किसी तरह पूरा करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं!

क्यों विवादित है ट्रंप का बयान?

कई दिनों के युद्ध के बाद अमेरिका को सीधे युद्ध के बजाय वार्ता का रास्ता अपनाना पड़ा। इस्लामाबाद बैठक हो या स्विट्जरलैंड बैठक, ईरान अपनी शर्तों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरान की शर्तों को पूरा करते हुए अमेरिका ने पहले ईरान की संपति को फ्रीज करना शुरू कर दिया है और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान बचकाना और विवादित स्पष्ट होता है।

वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में उच्च-स्तरीय वार्ता चल रही है, जो अब तक सकारात्मक दिशा में बढ़ती दिख रही है। भू-राजनीतिक मोर्चे पर ईरान ने अपनी ह्यएक्सिस ऑफ रेसिस्टेंसह्न (जिसमें हिजबुल्लाह, हूती जैसे सहयोगी समूह शामिल हैं) के जरिए क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया है। इस रणनीतिक स्थिति के कारण अमेरिका सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए बातचीत और कूटनीतिक समाधान का रास्ता अपनाने पर जोर दे रहा है।

ईरान में परमाणु निरिक्षण पर क्या बोले ट्रंप?

समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के निरीक्षकों की तैनाती को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ईरान सैद्धांतिक रूप से इसके लिए पहले ही सहमति दे चुका है। उन्होंने दावों को खारिज करते हुए कहा कि निरीक्षण के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और अगर स्थिति इसके विपरीत होती तो वह बातचीत रद्द कर देते।

पाकिस्तानी वायुसेना की बढ़ी चिंता

तेजस एमके 1ए की मारक क्षमता, चीन के जे-10सी जेट पर भारी

नई दिल्ली। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा चीन के हथियारों पर निर्भर करता है, जहां उसकी 85प्रतिशत रक्षा आवश्यकताएं चीनी आयात से पूरी होती हैं। हालांकि, इन चीनी हथियारों की विश्वसनीयता और युद्धक क्षमता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, जैसा कि बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा गया था, जब भारतीय हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की गई चीनी मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित हुए थे।

अब, भारत के स्वदेशी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट तेजस एमके1ए ने चीन के जे-10सी जेट, जिस पर पाकिस्तान अपनी वायुसेना की शक्ति का बड़ा आधार मानता है, को कई महत्वपूर्ण मामलों में पछाड़ दिया है। जे-10सी, जिसे बांग्लादेश जैसे देश भी खरीदने पर विचार कर रहे हैं, की तुलना में तेजस एमके1ए की हालिया रिपोर्ट ने चीनी जेट की क्षमताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

तेजस एमके1ए की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस) है, जो दुश्मन के रडार पर किसी विमान की दृश्यता को निर्धारित करता है। तेजस एमके1ए का आरसीएस मात्र 0.5 वर्ग मीटर है, जबकि चीनी जे-10सी और जेएफ-17 जैसे फाइटर जेट्स का आरसीएस 1 से 1.5 वर्ग मीटर के बीच है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार पर तेजस चीनी जेट्स की तुलना में आधे से भी कम दिखाई देगा, जिससे उसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। 0.5 वर्ग मीटर का आरसीएस तेजस एमके1ए को सेमी-स्टील्थ फाइटर जेट की श्रेणी में खड़ा करता है, जो इसे पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट्स, जैसे अमेरिकी एफ-35 (जिसका आरसीएस 0.0015 से 0.005 वर्ग मीटर है), के करीब लाता है। सरल शब्दों में कहें तो, जहां 15 मीटर का एक फाइटर जेट दुश्मन के रडार पर मात्र एक क्रिकेट या टेनिस बॉल जितना दिखेगा, वहीं चीनी जेट्स कहीं अधिक बड़े और आसानी से डिटेक्ट किए जाने वाले होंगे, जिससे दुश्मन के लिए उनका पता लगाना अपेक्षाकृत आसान होगा।

ये तीन विशिष्ट खासियतें

कम आरसीएस, उन्नत एईएसए रडार और बेहतर बीवीआर मिसाइलें- मिलकर तेजस एमके1ए को एक दुर्जेय लड़ाकू विमान बनाती हैं, जो पाकिस्तान और चीन की वायुसेना के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है। भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए 180 तेजस एमके1ए जेट्स खरीदने की तैयारी में है। हालांकि, इन अत्याधुनिक जेट्स की समय पर आपूर्ति में एक बड़ी बाधा है। भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित इन जेट्स में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के एफ404 इंजन लगाए जाने हैं, लेकिन जीई कंपनी द्वारा इंजनों की डिलीवरी में ढिलाई बरती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, एचएएल ने कम से कम 30 जेट्स का निर्माण पूरा कर लिया है और उनका परीक्षण भी हो चुका है, बस इंजनों के आने का इंतजार है ताकि उन्हें उड़ान के लिए तैयार किया जा सके। इस विलंब के बावजूद, तेजस एमके1ए की तकनीकी श्रेष्ठता भारत की हवाई शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करती है।

दूर भी डिटेक्ट नहीं कर पायेगा दुश्मन

आरसीएस की इस शानदार खासियत के साथ-साथ तेजस एमके1ए एक अत्यंत उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (एईएसए) रडार से भी लैस है। यह रडार तेजस को दुश्मन के ठिकानों का आसानी से पता लगाने में सक्षम बनाता है, जबकि दुश्मन तेजस को दूर से भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यह एक ऐसी दोहरी क्षमता है जो तेजस को युद्ध के मैदान में एक निर्णायक बढ़त देती है। इसके अलावा, तेजस एमके1ए में भारत की स्वदेशी अस्त्र एमके1ए बियॉन्ड विजुअल रेंज (बवीआर) मिसाइलें तैनात हैं, जिनकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। इसकी तुलना में चीनी जे-10सी और जेएफ-17 जेट्स पर तैनात पीएल-15 मिसाइलों की रेंज लगभग 140-145 किलोमीटर है। इस प्रकार, तेजस एमके1ए न केवल दुश्मन के रडार से बचने, बल्कि उसे पहले देखने और अधिक दूरी से निशाना बनाने की भी बेहतर क्षमता रखता है।

'मैं मुश्किलों से गुजर रही हूं', पद्म भूषण मिलने के बाद अलका याग्निक हुई इमोशनल

नई दिल्ली। दिग्गज सिंगर अलका याज्ञनिक को हाल ही में राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. लेकिन जब वो अपना अवॉर्ड लेने पहुंची तो उन्हें देख लोग हैरान रह गए. दरअसल, सिंगर के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वो बेहद कमजोर नजर आई. यहां तक कि उन्हें किसी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा था. वहीं, अब पद्म भूषण मिलने के बाद अलका याग्निक ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया और हेल्थ को लेकर भी अपडेट दिया.

मुश्किलों से गुजर रहीं अलका याग्निक

अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर पद्म भूषण मिलने के बाद अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों के बारे में भी बात की. उन्होंने लिखा- 'पिछले दो सालों से मैं लाइमलाइट और पब्लिक अपीयरेंस से दूर रही हूं और अपनी जिंदगी के सफर के बारे में ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, आप में से कई लोग जानते थे कि मैं सेहत से जुड़ी मुश्किलों से गुजर रही हूं और इस दौरान आपका प्यार, दुआएं, मैसेज और अटूट साथ हर कदम पर मेरे साथ रहा.'

ईरान ने कहा- अब होर्मुज पहले जैसी स्थिति में कभी नहीं चलेगा

तेहरान। अमेरिका के साथ हालिया वार्ता के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर किसी भी गलतफहमी को दूर करने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक टेलीफोनिक हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला किया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने स्विट्जरलैंड यात्रा से वापस आने के बाद यह बात कही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि होर्मुज अब पहले जैसी स्थिति में कभी नहीं लौट पाएगा और इसका प्रबंधन ईरानी प्रशासन के ही जिम्मे रहेगा। गलिबाफ ने कहा कि सबको इस बात का पता होना चाहिए कि युद्ध से पहले होर्मुज से आवाजाही जिस तरीके से चल रही थी, अब वैसे नहीं चल पाएगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ईरान अमेरिका पर ना कभी विश्वास करता था और ना ही आगे कर पाएगा। वार्ता में ईरान और अमेरिका एक कोऑर्डिनेशन मकैनिज्म बनाने पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत कोई भी जहाज हॉटलाइन के जरिए संपर्क कर सकता है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने लेबनान में संघर्ष खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा कि नया प्रकोष्ठ ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते की पहली बड़ी परीक्षा होगी। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक के अनुसार, बर्गेनस्टॉक में हुई बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान के हालिया बयानों से पैदा हुई उलझन, नौवहन की आजादी सुनिश्चित करने के उपाय और लेबनान में तनाव बढ़ने से रोकने के तरीके शामिल थे। राजनयिक ने कहा कि बातचीत करने वालों ने भविष्य में संभावित परमाणु समझौते के पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि आने वाले दिनों में तकनीकी बातचीत जारी रहेगी।

अब नया होगा ब्रह्मोस मिसाइल का अवतार

नई दिल्ली। ब्रह्मोस मिसाइलों को और ज्यादा घातक बनाने के लिए इसके नए संस्करण पर काम जारी है। इस मिसाइल का नया अवतार ज्यादा लंबी दूरी तक निशाना साधने के साथ ही हल्का और दुश्मनों की नजर से बचने की अपनी अद्भुत क्षमता से लैस होगा। ये नए संस्करण देश की सटीक हमले की क्षमता को और ज्यादा धार दे सकते हैं और साथ वैश्विक हथियारों के बाजार में देश की स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

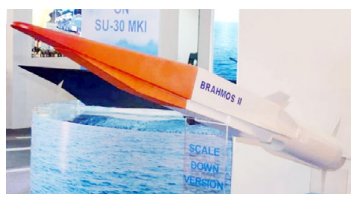

भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के तहत बनी इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर से ज्यादा है और इसे थलसेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल किया जा चुका है। शुरूआत में इसे 290 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य साधने के लिए तैयार किया गया था लेकिन मिसाइल तकनीक नियंत्रण प्रणाली (एमटीसीआर) में भारत को पूर्ण सदस्यता मिलने के बाद इसकी मारक क्षमता बढ़ाई क्योंकि इससे इसकी रेंज पर लगी पाबंदियां समाप्त हो गई थीं।

ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि भारत-रूस का यह संयुक्त उद्यम अगली पीढ़ी के संस्करण पर काम कर रहा है जिनमें कॉम्पैक्ट ह्यब्रह्मोस-एनजीह्न और भविष्य के लिए अधिक दूरी तक मार करने वाले संस्करण शामिल हैं।

कागजों पर गांव, हकीकत में शहर

नई दिल्ली। भारत में शहरीकरण का दायरा अब पारंपरिक प्रशासनिक सीमाओं को लांघ चुका है। देश के अनगिनत क्षेत्र कागजों पर भले ही आज भी गांव दर्ज हों, लेकिन धरातल पर वे पूरी तरह शहरों में बदल चुके हैं।

इन इलाकों में खेती पर निर्भरता बेहद कम हुई है, क्रांकीट का दायरा बढ़ गया है और यातायात का आधुनिक नेटवर्क तैयार हो चुका है। इस जमीनी बदलाव को देखकर केंद्र सरकार अब केवल शहरी और ग्रामीण के पुराने वर्गीकरण से आगे बढ़कर एक तीसरी नई श्रेणी फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट्स (कार्यात्मक शहरी बस्तियां) बनाने पर विचार कर रही है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत कार्यरत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) की ताजा रिपोर्ट में नए नेशनल सेटलमेंट क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई है। इस अध्ययन को प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में भारत में शहरीकरण को केवल जनगणना कस्बों और वैधानिक कस्बों के चश्मे से देखा जाता है, जो वास्तविक स्थिति को दशार्ने में नाकाफी है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के आधार पर अनुमानों के

मुताबिक, साल 2025 तक भारत की करीब 84 प्रतिशत आबादी शहरी बस्तियों में निवास कर रही थी, जबकि सरकारी कागजों में आंकड़ा महज 36 प्रतिशत के आसपास ही सिमटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में इसतरह के सैकड़ों गांव हैं, जो पूरी तरह शहरी सुख-सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन उनका प्रशासनिक संचालन आज भी ग्रामीण व्यवस्था के तहत हो रहा है। इस भौगोलिक और प्रशासनिक विसंगति को दूर करने के लिए सरकार उपग्रहों से प्राप्त नाइट-टाइम लाइट यानी रात के समय चमकने वाली रोशनी के डेटा का इस्तेमाल कर रही है, ताकि शहरों के वास्तविक फैलाव का सटीक आकलन किया जा सके। इसके अलावा सरकार टियर-2 से लेकर टियर-5 तक के शहरों के लिए एक समान वर्गीकरण को भी अंतिम रूप दे रही है, जिससे उनके आकार और जरूरत के हिसाब से सही नीतियां, निवेश और विकास योजनाएं तैयार की जा सकें। सरकार की इस नई पहल से देश के तेजी से बदलते आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को एक सही और व्यावहारिक दिशा मिलने की उम्मीद है।

ताजा खबर

संक्षिप्त

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा-6वीं प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम की तिथियां घोषित

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा-6वीं में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी है। विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथियों की भी घोषणा कर दी है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा-6वीं प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। विकासखंड स्तर पर 30 जून 2026 को, जिला स्तर पर 2 जुलाई 2026 को, राज्य स्तर पर 3 जुलाई 2026 को, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह एवं आरक्षित वर्ग के लिए 4 जुलाई 2026 को तथा आरक्षित दिवस 6 जुलाई 2026 को काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग संबंधित जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ही आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी वेब पोर्टल https://eklavya.cg.nic.in पर मेरिट सूची, काउंसलिंग केंद्र, दस्तावेजों की सूची तथा अन्य विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को मूल अंकसूची (मार्कशीट), निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है।विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in चेक करते रहें ताकि किसी भी प्रकार की सूचना से वंचित न रहें। अधिक जानकारी के लिए ई-मेल eklavya.ctd@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।यह सूचना आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, ब्लॉक-4डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नव रायपुर अटल नगर द्वारा जारी की गई है।

अल-नीनो के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ली छत्तीसगढ़ की खेती-किसानी की जानकारी

रायपुर। अल-नीनो के प्रभाव से इस बार मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन-तिलहन पर जोर, बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। इस आशय की जानकारी कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी। बैठक वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक कृषि श्री राहुल देव, संचालक अनुसंधान डॉ. विवके त्रिपाठी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मंत्री श्री नेताम ने बताया कि प्रदेश में 22 जून तक औसत वर्षा महज 30.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो पिछले 10 वर्षों के औसत से 58.3 मिलीमीटर कम है। खरीफ बोनी का लक्ष्य 48.69 लाख हेक्टेयर है, लेकिन अभी तक केवल 2 प्रतिशत क्षेत्र में ही बोनी हो पाई है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में सरकार ने किसानों को संभावित घाटे से बचाने के लिए कई ठोस उपाय शुरू कर दिए हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने बताया कि कृषि विभाग ने कम अवधि वाली धान के किस्मों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहनी और तिलहनी फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। उच्चहन भूमि में अनाज के साथ दलहन-तिलहन फसलों को अंतरवर्तीय फसल के रूप में लगाने की सलाह दी जा रही है। धान की जगह दलहन-तिलहन फसलों की ओर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषक उन्नति योजना- छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

धान के बदले वैकल्पिक फसलों की खेती पर मिलेगी 15 हजार रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता

छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा- दलहन-तिलहन और मिलेट्स उगाने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2026 में कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलें लेने वाले किसानों के लिए भारी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान धान के बदले अन्य फसलें अपनाएंगे, उन्हें 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं खरीफ वर्ष 2026 में दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाजों (मिलेट्स) की खेती करने वाले कृषकों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि का लाभ अरहर, उड़द, मूंगफली और तिल फसलों के उत्पादन पर मिलेगा। इसी तरह मक्का, रागी और लघु धान्य जैसे कोदो-कुटकी भी शामिल किया गया है। इस विशेष योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं और अपनी उपज (धान) सहकारी समितियों के माध्यम से बेचते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल क्रॉप सर्वे/गिरदावरी के माध्यम से रकबे (भूमि क्षेत्र) की पुष्टि होने के बाद ही मान्य रकबे पर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

गत वर्ष 2025 में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के चलते अकेले सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले में ही बड़े पैमाने पर किसानों को लाभान्वित किया गया। जिले में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले 144 किसानों को 13 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। दलहन- तिलहन व अन्य फसल उगाने वाले 10 हजार 408 किसानों के खातों में 2 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ाारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के उप संचालक कृषि ने क्षेत्र के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या समिति प्रबंधक से तुरंत संपर्क करें। किसान भाई कैरी फॉरवर्ड या नए पंजीयन के समय धान के बदले अन्य फसल या दलहन-तिलहन फसल बोए गए रकबा के विकल्प का चयन कर अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं, ताकि समय पर प्रोत्साहन राशि उनके खातों में भेजी जा सके।

एल-नीनो की चुनौती को अवसर में बदलें किसान- कृषि विभाग

रायपुर। प्रदेश में इस वर्ष एल-नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। विभाग ने विशेष रूप से अपलैंड एवं कम जलधारण क्षमता वाली भूमि में धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। ये फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं तथा प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में किसानों के लिए जोखिम को कम करती हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत अपलैंड क्षेत्रों में धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अद्यतन जानकारी देने के दिए निर्देश

ग्रेड-3 व ग्रेड-4 भर्तियों की तैयारी तेज विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्योरा

रायपुर. प्रदेश में ग्रेड-3 और ग्रेड-4 के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को महानदी भवन में विभागीय सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक में सभी विभागों को अपने यहां रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से संचालित भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की।मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा अद्यतन रखें, ताकि भर्ती संबंधी प्रस्तावों और चयन प्रक्रिया में देरी न हो। उन्होंने लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय-सीमा में आगे बढ़ाने को कहा। राज्य सरकार हाल ही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक समान व्यवस्था लागू कर चुकी है। हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से अब इन श्रेणियों की भर्तियां कराई जाएंगी। ऐसे में विभागों से रिक्त पदों का ताजा ब्यौरा मंगाने को आगामी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। विभागवार रिक्तियों का आकलन पूरा होने के बाद चयन प्रक्रिया को और गति मिलने की संभावना है। बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, सुषमा सावंत, सोनमणि बोरा व शहला निगार, सचिव मुकेश कुमार बंसल, राहुल भगत, नेहा चम्पावत, रजत कुमार, अंकित आनंद, एस. प्रकाश, अविनाश चम्पावत, रीना बाबा साहेब कंगाले, आर.शंगीता, बसवराजु एस., राजेश सुकुमार टोप्पो, शम्मी आबिदी, मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, भुवनेश यादव व भीम सिंह मौजूद थे। सेवा सेतु से जुड़ीं ऑनलाइन सेवाएं

मुख्य सचिव ने सभी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सेवा सेतु से जोड़ने के निर्देश दिए। इससे नागरिकों को एकीकृत, पारदर्शी और सुगम सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान, पीएम प्रगति पोर्टल, इ-प्रगति सांजो स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, मनरेगा और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

विधानसभा सत्र 13 से

बैठक में 13 से 17 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जरूरी जानकारियां, जवाब, अभिलेख समय पर तैयार रखने और संबंधित अधिकारियों की विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे सदन की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

भर्ती की क्या है नई व्यवस्था

राज्य सरकार ने तृतीय (ग्रेड-3) और चतुर्थ (ग्रेड-4) श्रेणी की सरकारी भर्तियों के लिए एक समान व्यवस्था लागू कर दी है। अब विभागों से मांग-पत्र मिलने पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कॉमन परीक्षा और संकाय विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। भर्ती प्रक्रिया को सात समूहों में बांटा गया है। ग्रेड-3 के अंतर्गत पटवारी, सहायक ग्रेड-3, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, उप अभियंता, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, खाद्य निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, खेल अधिकारी, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर जैसे पद शामिल हैं। वहीं ग्रेड-4 में वाहन चालक तथा विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी पद शामिल किए गए हैं।

नया रायपुर में कल सीएम साय करेंगे टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नई उद्योग नीति के तहत नया रायपुर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 25 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसकी जानकारी उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सहयोग केंद्र में दी। लखनलाल देवांगन ने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार नए उद्योग प्रारंभ हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहां स्थापित हों और छत्तीसगढ़ के नौजवान, पढ़े-लिखे मजदूर भाइयों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। बुधवार को भाजपा के सहयोग केंद्र में उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगनने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान सहयोग केंद्र में करीब 60 से 70 आवेदन प्राप्त हुए। मंत्री ने समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मौके पर ही सुनवाई की गई। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज सहयोग केंद्र था, जिसमें लगभग 60 से 70 भाजपा कार्यकर्ता और अन्य लोग अपनी छोटी-बड़ी समस्याएं लेकर आए थे। उनके निराकरण का प्रयास किया गया है। कई आवेदन ऐसे भी होते हैं, जो संबंधित विभाग से जुड़े नहीं रहते। ऐसे आवेदनों को हम संबंधित विभाग में भेजते हैं और आने वाले समय में उनका भी निराकरण होगा। अलग-अलग दिनों में अलग-अलग सहयोग केंद्र आयोजित होते हैं। इसी क्रम में आज मैं सहयोग केंद्र में बैठा हूं और आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया है।

भाजपा ने मनाया डॉ. मुखर्जी का बलिदान दिवस

रायपुर. भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय एकात्म परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा देशहित में किए गए कार्यों को याद किया।

भाजपा रायपुर जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की भावना के साथ जम्मू-कश्मीर की विशेष व्यवस्था का विरोध किया। उनका मानना था कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उनके विचार और सिद्धांत आज भी राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर में लागू दोहरी व्यवस्था और परमिट व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष भारत की एकता के इतिहास में सदैव प्रेरणादायी रहेगा।

दरगाहों और उर्स में डीजे बैन वाले आदेश पर लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की ओर से 11 जून 2026 को जारी उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश की दरगाहों, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल, नाच-गाने समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे।

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई। दरअसल, वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के तमाम दरगाहों, उर्सों व मजहबी जलसों में डीजे पर रोक लगाई थी। जारी फरमान में नाच-गाना, डीजे और धूमाल के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने यह फरमान जारी किया था। वक्फ बोर्ड के इस फरमान से आहत सूफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद की ओर से वकील देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर कहा गया कि वक्फ बोर्ड का यह फरमान उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया गया है। वक्फ बोर्ड को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की बेंच ने आज इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के तर्क को वाजिब मानते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा जारी फरमान पर रोक लगा दी है।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना: साय सरकार उठाएगी श्रमिकों के बच्चों के पढ़ाई-लिखई का पूरा खर्च

3 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस, छात्रावास, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री तथा अन्य आवश्यक खर्चों का पूरा वहन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा। इससे श्रमिक परिवारों को बच्चों की शिक्षा के आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, इसी सोच के अनुरूप राज्य सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर और श्रमिक वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना भी इसी दिशा में एक प्रभावी पहल साबित हो रही है, जिससे श्रमिकों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग के पोर्टल www.shramevjayate.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 22 जून से प्रारंभ हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुविधा श्रम विभाग के पोर्टल, निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र तथा श्रमेव जयते एप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा—पशुपालन बन रहा है स्थायी रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम

मंत्री रामविचार नेताम ने 13 पशुपालकों को सौंपी दुधारू गाय

रायपुर. छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिखने की दिशा में राज्य सरकार की समग्र डेयरी विकास योजना प्रभावी साबित हो रही है। इसी कड़ी में विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पचावल में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन तथा मछली पालन मंत्री श्री रामविचार नेताम ने 13 चयनित पशुपालकों को एक-एक दुधारू गाय, साइलेज पशुआहार एवं खनिज मिश्रण वितरित कर उनके जीवन में नई उम्मीदों का संचार किया। इस अवसर पर मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल पशु उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पशुपालन आज किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का नहीं, बल्कि सम्मानजनक और स्थायी रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुका है। अब हर वर्ग को मिलेगा योजना का लाभ मंत्री श्री नेताम ने बताया कि पहले दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ केवल आदिवासी समुदाय तक सीमित था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इसे सभी वर्गों के लिए लागू कर दिया है। इससे अब अधिक से अधिक ग्रामीण परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समग्र डेयरी विकास योजना के तहत हितग्राहियों को केवल दुधारू गाय ही नहीं, बल्कि सफल डेयरी संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना के अंतर्गत साइलेज, संतुलित पशु आहार, खनिज मिश्रण, एक वर्ष का पशु बीमा, पशु निगरानी उपकरण तथा वैज्ञानिक पशुपालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे पशुपालक आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अधिक उत्पादन और बेहतर आय अर्जित कर सकें।इस मंत्री श्री नेताम ने पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में संचालित नियमित टीकाकरण, उपचार एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ पशुधन ही डेयरी विकास की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने पशुपालकों से मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण कराने तथा वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने साइलेज के उपयोग और उसके लाभों की भी विस्तार से जानकारी दी। ग्राम पचावल में दुधारू गाय प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के चेहरों पर झलकती खुशी इस बात का प्रमाण थी कि सरकारी योजनाएं जब सही हाथों तक पहुंचती हैं तो वे केवल सहायता नहीं देतीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को नई दिशा देती हैं। एक दुधारू गाय अब इन परिवारों के लिए नियमित आय, बच्चों की बेहतर शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मसम्मान का नया आधार बनेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) डेयरी सर्विसेज के सहयोग से संचालित समग्र डेयरी विकास योजना के माध्यम से चयनित हितग्राहियों को अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर डेयरी व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। साथ ही दूध संग्रहण एवं विपणन की मजबूत व्यवस्था विकसित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा रही है। जिले में बड़ी संख्या में परिवार इस योजना से लाभान्वित होकर स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं।

अभिषेक पोरेल पर लगे गंभीर आरोप

यौन शोषण के मामले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी पर रिपोर्ट हुई दर्ज

मुम्बई। इंडियन प्रीमियर लीग से नाम कमाने वाले दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप लगे हैं. अभिषेक पर एक युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.पश्चिम बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल के ऊपर शादी का झांसा देकर शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं. बीते मंगलवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि, कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में अभिषेक पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. अभिषेक पोरेल चंदननगर

के रहने वाले हैं.

अभिषेक पोरेल पर लगे यौन शोषण के आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक ने इन सभी आरोपों को गलत करार दिया है. 23 वर्षीय अभिषेक पोरेल इस समय बेंगलुरु में है. पुलिस के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने क्रिकेटर पर आरोप लगाया है कि, वो और अभिषेक पोरेल तीन साल से रिलेशनशिप में थे. इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया था. इसके बाद डेढ़ साल पहले दोनों के बीच में कुछ समस्याएं हुईं और पूरा मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा गया था. उस समय कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. अब एक बार फिर से इन दोनों के बीच पूरा मामला बिगड़ गया है.

मां के साथ पुलिस थाने पहुंची युवती

इस बार पुलिस के पास थाने में युवती अपनी मां के पहुंची और उसने अभिषेक पोरेल के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. इसमें युवती ने उन्हें साझी का झांस देकर उनके साथ यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है. इस पूरे मामले पर अब हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुंवर भूषण सिंह ने मोगरा पुलिस स्टेशन का दौरा कर इंस्पेक्टर-इन-चार्ज सौमेन बिस्वास और डीएसपी (क्राइम) अभिजीत सिंह महापात्रा के साथ मुलाकात की और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. इस पूरे मामले पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली है. इसके बाद उनकी ओर से इश मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया अवॉर्ड

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा को मंगलवार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवॉर्ड दिया। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित उन 65 लोगों में शामिल थे, जिन्हें दूसरे दूसरे चरण के पद्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया। हॉकी स्टार सविता पुनिया को भी पद्मश्री मिला।

टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हिटमैन के साथ 19 साल वाला संयोग हुआ है। दरअसल, रोहित शर्मा को न सिर्फ पद्मश्री सम्मान मिला, बल्कि मंगलवार को ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 साल पूरे किए। उन्होंने 23 जून, 2007 को इंटरनेशनल डेब्यू किया था। रोहित तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी अगवाई में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2024 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी।

एचपीसीए के पुखराज मान इमर्जिंग मेन्स टूनार्मेंट को चयनित

टीम-सी में मिली जगह, छह से बंगलुरु में टूनार्मेंट

धर्मशाला। एचपीसीए के युवा खिलाड़ी पुखराज मान का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा होने वाले इमर्जिंग मेन्स टूनार्मेंट-2026 के लिए किया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अगले छह से 24 जुलाई तक बंगलुरु में आयोजित होगी। खिलाड़ियों को पांच जुलाई की दोपहर तक प्रतियोगिता स्थल पर

रिपोर्ट करना होगा।

एचपीसीए के मानद सचिव मनुज शर्मा ने बताया कि पुखराज मान को टूनार्मेंट के लिए टीम-सी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह चयन खिलाड़ी की प्रतिभा और मेहनत का परिणाम है तथा इससे प्रदेश क्रिकेट को भी नई पहचान मिलेगी। एचपीसीए परिवार की ओर से पुखराज मान को इस उपलब्धि के लिए बधाई।

वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की तीन नंबर जर्सी

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर मंगलवार को रवाना हो गए। बीसीसीआई की ओर से उन्हें तीन नंबर जर्सी होटल भिजवाई गई, जिसे सूर्यवंशी काफी देर तक देखते रहे। सूर्यवंशी को जर्सी भारतीय टीम में थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु ने सौंपी। सूर्यवंशी ने सबसे पहले रघु के पैर छूए और उन्हें प्रणाम किया, फिर जर्सी ली। इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया। सूर्यवंशी बोले, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिस दिन पहली बार बल्ला थामकर मैदान पर कदम रखा था, आज वह सपना पूरा हो गया है।

हल्द्वानी में हिमाचल का डंका, नैहरनपुखर के खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो में झटके तीन पदक

गरली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 13वीं अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिमाचल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेया का रोशन किया है। परागपुर में टीम ड्रैगन के कोच प्रवीण कुमार तथा येलो बेल्ट जगमोहन सिंह ने बताया कि टीम ड्रैगन नैहरनपुखर के खिलाड़ी जतिन पठानिया ने रजत पदक, राहुल जामवाल ने रजत पदक और अंकित शर्मा ने कांस्य

पदक जीता।

गर्व की बात है

कोच प्रवीण कुमार ने खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण को दिया। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद क्षेत्र के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।

पाकिस्तान फिर शमार्सार! मात्र 86 पर हुआ ढेर, ऑस्ट्रेलिया ने 113 रनों से रौंदकर जीता मैच

खेल समाचार। पाकिस्तान महिला क्रिकेट आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है. अब ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 113 रनों के बड़े अंतर से हराकर शर्मसार कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम फातिमा सना की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है. पाकिस्तान को बांग्लादेश की टीम से भी हार का सामना करना पड़ा था. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 113 रनों की बड़ी हार ने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी शर्मसार कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रनों से चटाई धूल

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 21 ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मंगलवार रात हेडिंग्ले, लीड्स में खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई. उनके बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने मात्र 86 रनों पर ढेर हो गए.

ऑस्ट्रेलिया के लिए इन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल

इस मुकाबले में ऐलिस पेरी ने शानदार पारी खेली. उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की और 48 बॉल में 9 चौके और 1 छक्के के साथ 71 रनों की पारी खेली. उनके अलावा जॉर्जिया वॉल ने 39, एनाबेल सदरलैंड ने 27 और निकोला कैरी ने 26 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल, रमीन शमीम और नशरा संधू ने 2-2 विकेट हासिल किए. इस मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से एकमात्र बल्लेबाज मुनीवा अली थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने हिम्मत दिखाई. उन्होंने 25 बॉल में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 32 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अन्य कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाया और पाकिस्तान 13.4 ओवर में 10 विकेट खोकर 86 रनों पर ढेर हो गई.

ये टीमें हुईं वर्ल्ड कप से बाहर

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने अब तक टूनार्मेंट में कुल 4 मैच खेले हैं. इस दौरान उसे सभी चारों मैचों में हार मिली है. इसके साथ ही वो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से एलिमनेट हो चुकी है. पाकिस्तान के साथ-साथ ग्रुप ए से नीदरलैंड की टीम भी बाहर हो चुकी है. वहीं ग्रुप 2 से आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी हैं.

इन टीमों के पास अभी भी चांस

ग्रुप ए में अभी बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और भारत के पास मौका है कि वो सेमीफाइनल में जगह बना सकें. ये तीनों टीमें अभी भी सेमीफाइनल में जगह बनाने की रेस में हैं. वहीं ग्रुप बी से श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के पास मौका होगा कि वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकें.

टीम इंडिया कैसे बना सकती है सेमीफाइनल में जगह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से हार मिली थी. इस मैच में हार के बाद से उनके सेमीफाइनल में जगह बनाने के रास्ते मुश्किलों से भर गए हैं. अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह अपने बाकी बचे हुए दोनों मैच बड़े अंतर से जीतकर बना सकती है. भारतीय टीम अपने अगले दो मुकाबलों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से भिड़ने वाली है.

कारोबार

शेयर बाजार तेजी के साथ खुला

मुम्बई। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ खुला। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये बढ़त दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी से आई है। आज सुबह कारोबार शुरू होते ही आईटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी से भी बाजार उछला। सुबह 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 200.34 अंक बढ़कर 76,401.02 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई इंडेक्स 38.65 अंक उछलकर 23,862.75 पर पहुंच गया।

आज डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज, टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर सबसे अधिक उछले। दूसरी ओर व्यापक बाजार में मिश्रित रुख दिखा। निफ्टी मिडकैप 0.04 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 0.12 फीसदी नीचे आये। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी में करीब 1 फीसदी की बढ़त रही। इसके अलावा निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में भी अच्छी तेजी रही। दूसरी ओर निफ्टी मेटल, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में गिरावट रही। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और बातचीत की संभावना बनने से एशियाई बाजार ऊपर आया है।

चांदी 11000 रुपये हुई सस्ती

बाजार खुलते ही सोने की चमक भी पड़ी फीकी

मुम्बई। सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बुधवार को कमोडिटी मार्केट खुलते ही गोल्ड और सिल्वर के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत पिछले तीन दिनों में करीब 11,000 रुपये प्रति किलो तक गिर चुकी है। हफ्ते के तीसरे बिजनेस डे यानी बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार शुरू होते ही गोल्ड और सिल्वर के भाव में फिर गिरावट दर्ज की गई।

चांदी का वायदा भाव फिसलकर 2.22 लाख रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर करीब 1.44 लाख रुपये रह गई।

सोना कितना सस्ता

अगस्त वायदा अनुबंध में एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। सोना 1.17% फिसलकर 1,45,060 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, सुबह करीब 9:27 बजे एमसीएक्स चांदी वायदा भी 0.39% की गिरावट के साथ 2,25,490 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।

अमेरिकी बाजार से मिला जुला

अमेरिकी शेयर बाजार में मंगलवार को मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। तेल कीमतों में गिरावट से चक्रीय शेयरों को मजबूती मिली, जबकि बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में दबाव रहा। एसएंडपी 500 इंडेक्स 27.79 अंक यानी 0.4% गिरकर 7,472.79 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 148.01 अंक यानी 0.3% की बढ़त के साथ 51,712.71 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट में 351.33 अंक यानी 1.3% की गिरावट दर्ज की गई और यह 26,166.60 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, रसेल 2000 इंडेक्स 24.64 अंक यानी 0.8% चढ़कर 3,004.40 पर पहुंच गया।

क्या है घरेलू बाजार में कीमत?

घरेलू बाजार में भी कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। जुलाई 2026 डिलीवरी वाला एमसीएक्स चांदी वायदा 3,256 यानी 1.4% की गिरावट के साथ 2,22,578 प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं, अगस्त 2026 डिलीवरी के लिए सोने का वायदा भाव 2,159 गिरकर 1,44,370 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

अंतरराष्ट्रीय विनिमय दरों में बदलाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में विनिमय दरों में बदलाव के बीच दुबई के कमोडिटी एक्सचेंज के सीईओ ने बताया कि एक्सचेंज जल्द ही ऐसा सोना अनुबंध शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका निपटान उसी दिन किया जा सकेगा। इस कदम का मकसद सुरक्षित निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों को आकर्षित करना और दुबई के सोने के बाजार

में कारोबार को आसान व तेज बनाकर तरलता बढ़ाना है।

गोल्ड लोन की बढ़ी हिस्सेदारी

पिछले चार सालों में खुदरा ऋण बाजार में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इस दौरान खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में स्वर्ण ऋण का हिस्सा दोगुने से भी अधिक हो गया है। क्रेडिट ब्यूरो एक्सपीरियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी अवधि में वित्त कंपनियां ऋण देने वाली सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी बनकर सामने आई हैं। ये कंपनियां लगातार अपना विस्तार कर रही हैं और ऋण बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत कर रही हैं। गोल्ड लोन्स इन ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट में इस क्षेत्र की तेज रफ्तार वृद्धि को हाईलाइट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल खुदरा ऋण वितरण में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 के 18% से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 41% तक पहुंच गई है।

इस स्टॉक में लगा 8% का अपर सर्किट

मुंबई।ऑटो-टेक सप्लायर ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में बुधवार, 24 जून को जबरदस्त उछाल देखने को मिली. कंपनी के 5:1 बोनस इश्यू के एडजस्टमेंट के बाद, स्टॉक 8% से ज्यादा चढ़कर 52-हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गया. इस बीच, घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स में मिला-जुला रुख रहा. निफ्टी 50 मामूली बढ़त के साथ 0.04% बढ़कर 23,833.10 पर रहा, जबकि सेंसेक्स 48.37 अंक गिरकर 76,152.31 पर आ गया.

कंपनी के शेयर 2,814 पर खुले जबकि पिछली क्लोजिंग 16,086 थी. और ठरए पर 8.17% बढ़कर 3,044 प्रति शेयर के नए 52-वीक के हाई पर पहुंच गए. बाद में, स्टॉक 2,709 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था, जो 1.08% ज्यादा था, जबकि ठरए निफ्टी 50 बेंचमार्क 0.35% ऊपर था. रिटर्न के मामले में, स्टॉक ने एक हफ्ते में 8%, एक महीने में 10%, साल-दर-साल आधार पर 11% और पिछले साल में 24% का रिटर्न दिया है. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,841.29 करोड़ है. पिछले 5 सालों में, स्टॉक ने निवेशकों को 8,819.54% का रिटर्न दिया है.

7-8 फीसदी की वृद्धि दर जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष महेंद्र देव ने कहा कि भारत को 2047 तक ह्यविकसित भारतह्ण बनने के लिए सात से आठ फीसदी की निरंतर आर्थिक वृद्धि दर चाहिए। यह लक्ष्य निजी क्षेत्र के निवेश और मजबूत निर्यात वृद्धि पर बहुत अधिक निर्भर करता है। देव ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए यह बात कही।

देव ने जोर दिया कि विकसित भारत के लिए निवेश आवश्यक है। निजी क्षेत्र का निवेश और निर्यात वृद्धि दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के ह्यआत्मनिर्भर भारतह्ण के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। घरेलू बाजार को वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पाद गुणवत्ता बढ़ानी होगी। आत्मनिर्भर भारत नीति का अर्थ वैश्विक व्यापार से पीछे हटना नहीं है। इसका ध्यान देश की जनसांख्यिकीय और तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाने पर है। सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 100 वस्तुओं की पहचान की है। इन वस्तुओं का घरेलू विनिर्माण विदेशी सामान का स्थान ले सकता है। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता में सुधार के प्रयास भी जारी हैं। ये सभी प्रयास अर्थव्यवस्था को बाहरी कमजोरियों से बचाने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं।

महेंद्र देव ने साफ किया कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब आयात प्रतिस्थापन नहीं है। इसका उद्देश्य घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। देव ने वर्तमान खाद्य भंडार पर विश्वास व्यक्त किया। भारत के पास दालों का पर्याप्त भंडार है। यह घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकेगा। हालांकि, बाहरी कारक अभी भी आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करते हैं। पश्चिम एशिया युद्ध और अल नीनो के कारण चुनौतियां हैं। देव भारतीय रिजर्व बैंक के 6.6 फीसदी वृद्धि और 5.1 फीसदी मुद्रास्फीति के अनुमानों से सहमत हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं सहित कई जनहितैषी कार्यों को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार 960 करोड़ रुपए की योजनाओं सहित कई जनहितैषी कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को गति देते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालित रखने के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राज्य में शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूलों के उच्च स्तरीय उन्नयन की योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहुँच बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, किसानों के आर्थिक संबल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना की नई शर्तों, शुजालपुर (शाजापुर) में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3 हजार 580 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की निरंतरता तथा जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजना अंतर्गत गरीब जरूरतमंद, निराश्रित और निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में राशि 55 हजार रुपए प्रति कन्या के मान से दी जाती है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 1 लाख 72 हजार 905 हितग्राहियों को 989 करोड़ 80 लाख 62 हजार रुपए से अधिक सहायता राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, योजना महिला सशक्तिकरण की एक अहम योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब और जरुरतमंद अभिभावकों की कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्पन्न होता है। इस योजना से विवाह की वैधानिक आयु सुनिश्चित हो जाती है। यह योजना महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिये महत्वपूर्ण है। मंत्रि-परिषद ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहुँच एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन की योजना पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

स्वीकृति अनुसार वर्ष 2026-27 में 75 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल तथा 100 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। आगामी 2 वर्षों 2027-28 एवं 2028-29 में भी इसी प्रकार प्रतिवर्ष 75 माध्यमिक एवं 100 हाईस्कूलों के उन्नयन पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। साथ ही विद्यालयों के उन्नयन के लिए अनुमानित व्यय राशि 635 करोड़ 24 लाख रुपए के प्रस्ताव पर सहमति दी। विकसित मध्यप्रदेश@2047 के तहत वर्ष 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मापदण्डों के आधार पर जिला स्तर से मैपिंग अनुसार 315 हाई स्कूल एवं 214 हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है। सांदीपनि विद्यालयों के कैचमेंट एरिया में विद्यालयों का उन्नयन नहीं किया जाएगा। सांदीपनि विद्यालय के कैचमेंट एरिया में आने वाले विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में होने पर विद्यालय को अन्य आवश्यकता वाले स्थानों पर युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। उन्नत विद्यालय अपने वर्तमान भवन या अन्य शासकीय भवन में संचालित होंगे। आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किए जाएंगे। वास्तविक रूप से आवश्यक विद्यालयों की संख्या का आंकलन गति शक्ति पोर्टल, जनसंख्या एवं यू-डाइस के आंकड़ों के आधार पर की जायेगी।

राज्य में हाई स्कूल का सकल नामांकन दर (जीईआर) 75 प्रतिशत तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर 55 प्रतिशत है। कक्षा 8 से 9 में कक्षांतरण दर 77 प्रतिशत और कक्षा 10 से 11 में 68 प्रतिशत है। विद्यालयों की दूरी अधिक होने होने के कारण विद्यार्थियों का प्रवेश कम होता है या वे नियमित रूप से उपस्थित नहीं रह पाते, जिससे ड्रॉप आउट दर बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थियों की पहुँच में विद्यालय उपलब्ध कराकर उच्च नामांकन एवं निरंतरता सुनिश्चित करना इस निर्णय का मूल लक्ष्य है। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना अंतर्गत किसानों के हित में शर्तों की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार खरीफ एवं रबी सीजन के लिए पृथक-पृथक देय तिथि (ड्यू डेट) नहीं रखते हुए उसके स्थान पर वार्षिक एकल ऋण सीमा रखी जाएगी, जिसमें नगद एवं वस्तु ऋण की उप-सीमा निर्धारित रहे। योजनान्तर्गत देय तिथि (ड्यू डेट) कृषकों को स्वीकृत वार्षिक एकल लिमिट से प्रथम ऋण आहरण से 12 माह निर्धारित की जाएगी और अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को 1.25 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रदेश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध बहुउददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना वर्ष 2012-13 से निरन्तर लागू है। योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से रुपए 3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। योजना में राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष बेस रेट के साथ-साथ डयू डेट आदि का निर्धारण किया जाता है और निर्धारित बेसरेट में से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली ब्याज सहायता को कम करते हुये शेष राशि राज्य शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, जिससे कृषकों को प्रदेश में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध होता है।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में सत्र 2026-27 में शुजालपुर (शाजापुर) में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति दी। स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक वर्ग के 9 पद और अशैक्षणिक वर्ग के 8 पद, इस प्रकार कुल 17 पदों के सृजन और व्यय राशि 2 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर में विधि पाठ्यक्रम (एलएलबी तीन वर्षीय) एक संकाय के रूप में संचालित है। बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया के 2008 के 'लीगल एजुकेशन रूल्स' के अनुसार मान्यता के लिए विधि पाठ्यक्रमों को संकाय के स्थान पर पृथक शासकीय विधि महाविद्यालय में संचालित किया जाना आवश्यक है। इसी आधार पर शुजालपुर में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया जा रहा है। मंत्रि-परिषद ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए से अधिक की संबंधित योजना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन, कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति का 16 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए 3 हजार 580 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंश पूँजी के रूप में उपलब्ध करवाये जाने का निर्णय लिया है।

नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, सरल संयोजन पोर्टल से करें ऑनलाइन आवेदन

- भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये सरल और सुविधाजनक तरीके से त्वरित नवीन बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में घर बैठे ही नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विगत जुलाई 2023 से शुरू किये गये ऑनलाइन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से अब तक भोपाल शहर एवं भोपाल ग्रामीण वृत्त में एक लाख 21 हजार 619 नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में 6 लाख 11 हजार से अधिक नए कनेक्शन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक दिये गए हैं।

आधुनिक एवं स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में जीआरपी का महत्वपूर्ण कदम

- भोपाल। बदलते अपराध स्वरूपों और आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप पुलिस बल को अधिक सक्षम, तकनीकी रूप से दक्ष एवं जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) द्वारा आयोजित 15 दिवसीय विशेष पुलिस प्रशिक्षण शिविर का समापन विशेष पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री संजीव कुमार शमी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल, भोपाल श्री राजाबाबू सिंह के मुख्य आतिथ्य में पी.टी.आर.आई. प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में सम्पन्न हुआ।

कौशल विकास और पर्यटन विभाग युवाओं के रोजगार के लिये समन्वयपूर्वक करें प्रबंध: मुख्यमंत्री

आईटीआई में 2 वर्ष में 5 हजार 840 सीट्स संख्या की वृद्धि

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में सतत रूप से नवाचारों की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में धार्मिक, प्राकृतिक, पुराधरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध है। पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनाने और विभिन्न व्यंजनों का आनंद दिलवाने के लिए कार्य की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में इन कार्यों से रोजगार मिलेगा।

कौशल विकास और रोजगार विभाग का पर्यटन विभाग से तालमेल स्थापित कर यह कार्य संभव है। इसी तरह के रोजगारपरक कार्य दिलवाने के लिए विभिन्न विभाग नवाचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार विभाग की गतिविधियों की बैठक में समीक्षा की। बैठक में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल,मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में फैक्ट्री परिसर में भी प्रशिक्षण संस्था संचालित की जा सकती है। उद्योगों की जरूरत को देखते हुए आवश्यक ट्रेड में प्रशिक्षण के प्रबंध किए जाएं। कौशल विकास और रोजगार दिलवाने के विभिन्न विभागों के कार्यों का समग्र प्रतिवेदन भी तैयार किया जाए। विभिन्न विभाग संचालित योजनाओं से दी जा रही सेवाओं और सृजित नए रोजगारों का विवरण भी संकलित करें ताकि इस क्षेत्र की उपलब्धि एक नजर में दर्शाई जा सके। शासकीय और निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे रोजगार, राज्य की ही उपलब्धि है।

विभाग के प्रमुख नवाचार

बैठक में विभाग स्तर पर किए गए विभिन्न नवाचारों की जानकारी दी गई। परम फाउंडेशन के अंतर्गत 10 आईटीआई का संचालन एक विशेष नवाचार है। प्रतिमाह युवा संगम के आयोजन, महिला ड्राइविंग प्रशिक्षण, प्रतिभा सम्मान, वर्ष 2025 से आईटीआई में 30 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने, विद्यार्थियों को विदेशी भाषा प्रशिक्षण और इसके माध्यम से रोजगार की संभावना बढ़ाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण का लाभ युवाओं को दिलवाया गया है।

कौशल विकास क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां

बैठक में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। इनमें वर्ष 2025 में 490 दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को संस्थाओं में प्रवेश, गत 2 वर्ष में प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से 18 हजार 403 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार, वर्ष 2025 में आईटीआई चलो अभियान में अब तक के सर्वाधिक 49 हजार 402 प्रवेश, यूएन वूमेन के सहयोग से 12 जनजातीय बहुल जिलों की 2127 महिलाओं को प्रशिक्षण, प्रदेश के तीन प्रशिक्षण अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, युवा संगम से सवा तीन लाख आवेदकों को लाभ, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में वर्ष 2024 से रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाइल जैसे 9 आधुनिक लॉंगटर्म कोर्स का संचालन, 10 संभागीय आईटीआई के लिए हब इंस्टीट्यूट के रूप में व्यवस्थाएं कर ऑन-द-ऑब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सहायता दिलवाई जा रही है। वर्ष 2025 में आई टी आई में 3484 सीटों की वृद्धि की गई। वर्ष 2026 में 2356 सीटों की वृद्धि हुई। इस तरह दो वर्ष में 5840 सीट्स बढ़ी हैं। आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में इस वर्ष 10 प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त कौशल विकास और रोजगार विभाग युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी का अवसर दिलवा रहा है। इस क्रम में वर्ष 2024 में फ्रांस में हुई अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्किल स्पर्धा में मध्यप्रदेश के संस्कार शर्मा ने सायबर सिक्योरिटी स्किल में मेडालियम ऑफ एक्सीलेंस हासिल किया। क्षेत्रीय स्पर्धा में 44 पदक और राष्ट्रीय स्पर्धा में 8 पदक प्राप्त करने की उपलब्धि भी मध्यप्रदेश को मिली है। ग्लोबल पार्क, भोपाल में वर्ष 2026-27 में 3 हजार सर्टिफिकेशन का लक्ष्य तय किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

- प्रदेश में कौशल विकास की गतिविधियां निरंतर संचालित हों।
- औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप कोर्स डिजाइन कर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए।
- खान-पान तैयार करने (पाक कला प्रशिक्षण) और गाइड के प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी जाए।
- कोसा वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रदेश में अधोसंरचना उपलब्ध है। युवाओं को उद्यानिकी विभाग के सहयोग से शहतूत उत्पादन जैसे कार्यों से जोड़ा जाए। रेशम उत्पादन की संभावनाओं पर भी कार्य किया जाए।
- गुना जिले में जैकेट बनाने का कार्य एक आदर्श मॉडल है। आर्थिक लाभ दिलवाने वाली अनेक गतिविधियां घर से ही संचालित की जा सकती हैं। लघु और कुटीर उद्योगों से युवाओं को जोड़ने के ठोस प्रयास किए जाएं।

आदिरंग में बिखरे जनजाति संस्कृति और उमंग- उल्लास के रंग

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, मध्यप्रदेश सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजातीय समाज के विकास और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण का कार्य वर्ष 2022 से प्रारंभ हुआ है। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है। जनजातीय नायकों के सम्मान में प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में राजा भभूत सिंह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती की स्मृति में विभिन्न आयोजन किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के निकट ग्राम अचारपुरा में पांच दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महोत्सव में जनजातीय कलाकारों द्वारा तैयार शिल्प कृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इन कलाकृतियों को पारंपरिक शैली में आधुनिकता के साथ पेश करने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलाकारों से आत्मीयता के साथ चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय शिल्प का डंका देश-विदेश में बज रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विरासत से विकास के अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे देश में लोक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रगति के कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु गत सप्ताह मध्यप्रदेश भ्रमण पर रहीं और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती ने गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयाँ प्रदान की। दुनिया ने उनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम को देखा। रानी दुर्गावती ने गौंडवाना क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्कालीन मुगल सत्ता के विरुद्ध अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्र गौरव के लिये संघर्ष करते हुए प्राणों की आहूति दे दी। आज हम रानी कमलापति के पराक्रम के क्षेत्र भोपाल में वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य को नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अनेक जनजातीय वीरों की धरती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदिरंग शिल्पकार महोत्सव में जनजातीय कलाकारों ने प्रकृति के माध्यम से हमारे जीवन में उत्सव के रंग भरने का प्रयास किया है। एनआईडी ने जनजातीय परंपरागत कला को नए आयाम पर पहुंचाया है। कला-संस्कृति के माध्यम से कई लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि का सूर्य उदय होगा। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चहुंमुखी विकास कर रहा है।

राष्ट्रीय फलक पर पहचान बना रही जनजातीय कला

जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ संयुक्त तत्वावधान में मनाये जा रहे इस आदिरंग शिल्पकार महोत्सव में जनजातीय समाज की प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। एनआईडी के समन्वय से मध्यप्रदेश की परंपरागत शिल्प को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। जनजातीय कार्य विभाग के प्रयासों से जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में इस दिशा में बेहतर कार्य किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की निदेशक डॉ. विद्या राकेश ने कहा कि आदिरंग सिर्फ एक शिल्पकार महोत्सव नहीं, बल्कि डिजाइन, कल्चर, कम्युनिटी और एम्पॉवरमेंट को जोड़ने का एक प्रयास है। गत कुछ वर्षों में एनआईडी ने मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के साथ मिलकर बैगा, गौंड, भील और अन्य जनजातीय समाज के बीच डिजाइन डेवलपमेंट कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इनके माध्यम से शिल्पकारों को डिजाइन अवेयरनेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिग, पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसे विषयों से परिचित करवाया गया है ताकि उनकी कला को वर्तमान बाजार की जरूरतों के हिसाब से लिंक किया जा सके। एनआईडी ने जनजातीय समुदायों की संस्कृति का दस्तावेजीकरण भी किया है। यह उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के नए अवसर भी विकसित होते हैं। एनआईडी जनजातीय समाज को वोकल फॉर लोकल से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। जनजातीय कलाकार श्री गगन सिंह मरावी ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आदिरंग महोत्सव में गौंड चित्रकारों को नई चीजें सीखने का मौका मिला। भील चित्रकार श्रीमती गोरिया भाबोर ने बताया कि इस महोत्सव में हमें अपनी चित्रकार को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है।

समारोह में जनजातीय कला, शिल्प और आजीविका संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। पांच दिवसीय महोत्सव में मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 140 से अधिक जनजातीय शिल्पकार शामिल हुए। भील, गोंड, बैगा सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों के शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक कला, शिल्प और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। महोत्सव के दौरान आयोजित डिजाइन हस्तक्षेप कार्यशालाओं में शिल्पकारों ने एनआईडी मध्यप्रदेश के संकाय सदस्यों एवं छात्र स्वयंसेवकों के सहयोग से बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पाद विकसित किए। समापन समारोह में कार्यशालाओं के दौरान विकसित उत्पादों और डिजाइन अवधारणाओं की विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई।

कार्यक्रम में विधायक श्री विष्णु खत्री, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रामदास रौतेल, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री भगत सिंह नेताम, श्री मंगल सिंह धुर्वे, प्रमुख सचिव जनजातीय विकास श्री गुलशन बामरा, आयुक्त श्री तरुण राठी और अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

प्रदेश में आधार सेवा अधोसंरचना का हुआ विस्तार

भोपाल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा मध्यप्रदेश में आधार सेवाओं को नागरिकों तक अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ पहुंचाने के लिए आधार सेवा अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इस पहल से प्रदेश के नागरिकों को आधार नामांकन एवं अद्यतन संबंधी सेवाएं अपने निकट ही उपलब्ध हो सकेंगी। वर्तमान में यूआईडीएआई द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र (एएसके) प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, विदिशा एवं भिण्ड में संचालित हैं। ग्वालियर और शिवपुरी में मंगलवार से आधार सेवा केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार प्रदेश के 10 जिलों में आधार सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। आधार केंद्रों पर नागरिकों को आधार नामांकन, डेमोग्राफिक एवं बायोमेट्रिक अपडेट सहित विभिन्न आधार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए इन केन्द्रों पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए बुधवार, 24 जून 2026 को राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान ₹सेफ क्लिक 2.0₹ का शुभारंभ करेंगे। मध्यप्रदेश पुलिस के इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है जिससे वे सुरक्षित साइबर व्यवहार अपना सकें। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान साइबर सुरक्षा और बाल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए 'इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन' के साथ एक समझौता ज्ञापन (टङ्कव) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, स्कूली बच्चों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक विशेष साइबर जागरूकता बुकलेट और 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के जागरूकता वीडियो का विमोचन भी किया जाएगा। इस अवसर पर जनसामान्य को सरल एवं प्रभावी ढंग से जागरूक करने के लिए साइबर सुरक्षा पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियों के संचालन के लिए 'साइबर जागरूकता रथ' को हरी झंडी दिखाकर (फ्लैग ऑफ) रवाना करेंगे। यह रथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर नागरिकों तक सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और सतर्कता का संदेश पहुंचाएगा। इस अभियान के तहत मध्यप्रदेश पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक वेबसाइट पर दें और एक सुरक्षित डिजिटल समाज के निर्माण में सहभागी बनें।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।